राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 37 ▪ अंक 2 ▪ जून–जुलाई 2016 ▪ ₹10 ▪ पृष्ठ 40

जम्मू में अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न

अभिनवगुप्त की प्रासंगिकता

कब तक मिलेगा केरल की निर्मया को इंसाफ़...?

जम्मू कश्मीर : संवाद से ही भविष्य की राह मुमकिन

देश जानने की अनोखी पहल

जम्मू में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक की झलकियाँ

नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय बिदरे को सम्मानित करते हुए; साथ में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव जैन, परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर एवं अन्य

रराष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक का उद्घाटन करते परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय बिदरे एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 37, अंक 2
जून-जुलाई 2016 संयुक्तांक

संपादक-मण्डल :
आशुतोष
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
छात्रशक्ति भवन, 26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002; फोन : 011-23216298
वेबसाइट : www.abvp.org

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/chhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली-110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ.आई.ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में...

पृष्ठांक

4 संपादकीय

5 देश के सभी राज्यों में लागू हो 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा'

6 जम्मू-कश्मीर : संवाद से ही भविष्य की राह मुमकिन

10 अभिनवगुप्त की प्रासंगिकता

13 राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा

15 जम्मू में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक में पारित प्रस्ताव

19 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के पीछे वामपंथ

20 'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' : कमज़ोर पटकथावाली साहसी फ़िल्म

22 शिक्षा की स्वायत्तता

24 कब तक मिलेगा केरल की निर्भया को इंसाफ़...?

27 देश जानने की अनोखी पहल

32 मंज़िलें और भी हैं...

34 योग से मज़बूत हुई भारत की साख

36 नेशनलिज़्म-राष्ट्र-राष्ट्रीयता-राष्ट्रवाद

संपादकीय

नौ जुलाई परिषद् का स्थापना-दिवस है। 1948 में अनौपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ होने के एक वर्ष बाद इस दिन संगठन का पंजीयन हुआ। देशभर में इससे जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नये शिक्षा-सत्र का प्रारंभ होने के कारण यह समय सक्रियता का होता है। पिछले सत्र के मूल्यांकन और नये सत्र की योजनाओं के साथ कार्यकर्ताओं के नये सिरे से कर्मक्षेत्र में उतरने का अवसर है यह। सभी इकाइयों ने अपने-अपने लक्ष्य निश्चित किये होंगे और उन्हें पूरा करने में मनोयोग से लगे होंगे, यह विश्वास है।

इस वर्ष की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् 28 से 30 मई तक जम्मू में आयोजित हुई। इससे पूर्व 1998 में इसका आयोजन हुआ था। पिछली बैठक की पृष्ठभूमि में जहाँ भविष्य की चिन्ता थी, वहीं इस बार भविष्य के प्रति आश्वस्ति का भाव था। अभाविप ने जम्मू काश्मीर के विषय को सदैव प्राथमिकता में रखा है। 1990 में काश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन की पीड़ा को देशभर में पहुँचाने के लिये परिषद् ने 'चलो काश्मीर' का नारा दिया। दस हज़ार से अधिक नौजवान परिषद् के आह्वान पर जम्मू पहुँचे और वहाँ से काश्मीर की ओर कूच किया। ऊधमपुर से आगे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस लालचौक पर पहुँचकर वे तिरंगा फहराना चाहते थे, किन्तु सुरक्षा कारणों से जा नहीं सके, उसी लाल चौक पर आज लोग देर रात तक बेफ़िक्र चहल-कदमी करते देखे जा सकते हैं। आतंकवाद आज हार चुका है। अलगाववाद आखिरी साँसें ले रहा है। क्षीरभवानी मन्दिर के मेले में और शादीपुरा में आयोजित महाकुंभ में 40 हज़ार लोगों का देशभर से उमड़ना साबित करता है कि राज्य में निर्णायक परिवर्तन आया। साथ ही यह भी, कि देश इस परिवर्तन के साथ खड़ा है।

यह ठीक है कि राज्य में स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। लेकिन वहीं यह सावधानी भी ज़रूरी है कि ज़रा-सा संतुलन बिगड़ते ही सुधार की गति ठहर सकती है और मामला पटरी से उतर सकता है। राज्य के राजनैतिक-सामाजिक नेतृत्व को अपने-आपको यह विश्वास दिलाना होगा कि आज जो माहौल बदला है उसके पीछे समझौतापरस्ती नहीं बल्कि समझौताविहीन नीति है। दशकों तक परखने के बाद लोगों ने यदि निर्णायक भूमिका तक पहुँचाया है तो सिर्फ़ इसलिये कि उनकी कथनी और करनी के एक होने का विश्वास जमा है। यह विश्वास न टूटे, यह भी उनकी ही ज़िम्मेदारी है।

बुद्धिजीवी इस परिवर्तन के स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय तक तमाम कारण गिना सकते हैं। लेकिन सौ बात की एक बात, यह तब संभव हुआ जब मध्यस्थों को हटाकर जनता से सीधे संवाद के रास्ते खोले गये। जम्मू काश्मीर का प्रश्न न हिंदू-मुसलमान का प्रश्न है और न ही भाजपा-काँग्रेस अथवा पीडीपी-नेशनल काँफ्रेंस का। यह भारत-पाकिस्तान के बीच का अनिर्णित प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न दिल्ली और काश्मीर के बीच की मानसिक दूरी का है जिसे कुछ राजनैतिक ठेकेदारों ने अपने निजी स्वार्थों के ख़ातिर पैदा किया और बनाए रखा है।

जिन्होंने यह दूरी पैदा की, और जिन्होंने इसे पनपने का मौका दिया– दोनों ही आज परिदृश्य में नहीं है। उनके बोझ को ढोने से अच्छा है संवाद की इस पहल को ही और मज़बूत बनाने के प्रयास किये जायें। विदेशी समर्थन पर भारत-विरोध की राजनीति करनेवाले अलगाववादियों को अलग-थलग कर विकास का उचित हिस्सा राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचना सुनिश्चित किया जा सका तो समाधान संभव है।

अभाविप जम्मू काश्मीर ही नहीं , बल्कि पूरे देश के विषय में भी इसी तरह सोचती है इसीलिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास-जैसे बुनियादी मुद्दों पर चिन्तन राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक का मुख्य भाग होता है। बैठक में इनसे जुड़े सात प्रस्ताव पारित किये गये जो इस अंक में संकलित हैं।

काश्मीर की पहचान आचार्य अभिनवगुप्त का सहस्राब्दी समारोह देश मना रहा है। उनकी प्रासंगिकता पर एक आलेख दिया गया है। साथ ही यह मास डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के स्मरण का भी है। प्रजा परिषद् आंदोलन के पश्चात् हुई उनकी गिरफ़्तारी और अंततः बलिदान ने जम्मू काश्मीर की भारत के साथ एकात्मता का मार्ग प्रशस्त किया। देवेश कुमार का शोधपरक लेख उस समय की परिस्थिति को समझने में पाठकों की मदद करेगा।

अभाविप को गढ़नेवाले स्व. श्री बाल आपटे जी की पुण्य तिथि 17 जुलाई को है। उनका स्मरण हम सभी को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिये सदैव प्रेरणा देता रहेगा। अन्य सभी स्थायी स्तंभों के साथ छात्रशक्ति का यह अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

शुभकामना सहित,

आपका,
संपादक

देश के सभी राज्यों में लागू हो 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा'

विश्वविद्यालयों को राष्ट्र-निर्माण व सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बनाने पर हुई चर्चा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की जम्मू में हुए तीन-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक की शुरूआत **'राष्ट्रशक्ति - छात्रशक्ति'** व **'कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी'**-जैसे नारों से हुई। बैठक में शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने, विश्वविद्यालयों को राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बनाने की बात को प्रमुखता से रखा गया। साथ ही, अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस नीतियाँ बनाने तथा चिकित्सा-शिक्षा की अनियमितताओं को दूर करने संबंधी प्रयास किए जाने का मुद्दा उठा। इस दौरान परिषद् ने एमबीबीएस और बीडीएस दाखिलों के लिए नीट (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) का समर्थन करते हुए सभी राज्यों से इसे लागू करवाने पर जोर दिया। जम्बूलोचन हॉल में हुए इस बैठक में देशभर से 250 से अधिक पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बतादें कि 18 वर्ष पश्चात् जम्मू में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक का आयोजन हुआ।

परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रवादी आंदोलन को मज़बूत बनाने के लिए युवाओं की भूमिका अहम है। परिषद् 28 लाख सदस्यों के साथ बड़े छात्र संगठन के रूप में उभरकर सामने आया है और आगामी वर्ष में यह संख्या 50 लाख के पार होगी। युवाओं में राष्ट्रप्रेम तथा नैतिकता का पुट समावेशित करने की दिशा में ज़रूरी है कि शिक्षण-संस्थान अपनी भूमिका को समझें। इस क्रम में विश्वविद्यालयों में बुनियादे ढाँचे के साथ ज्ञान, शोध, गुणवत्ता और आर्थिक ढाँचे को मज़बूत बनाने की दिशा में काम किए जाने की भी ज़रूरत है। डॉ. ठाकुर ने जम्मू-काश्मीर प्रांत के राष्ट्रवादी विद्यार्थियों का विपरीत परिस्थितियों में भी सतत् राष्ट्रहित में कार्य करने की भावना का हृदय से अभिनन्दन किया।

इससे पूर्व सुबह के सत्र में परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक की शुरूआत की। बैठक में राष्ट्र के विकास में सहायक होनेवाली शिक्षा के विकास पर चर्चा हुई। इसके अलावा, एमसीआई और डीसीआई में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की वकालत भी की गई। मेडिकल कॉलेज़ों की मनमानी पर बोलते हुए प्रतिनिधियों ने साफ़ किया कि बड़ी संख्या में ऐसे निजी मेडिकल कॉलेज़ हैं जो एमसीआई के मापदण्डों को पालन नहीं कर रहे हैं। यही हाल डेंटल कॉलेज़ों में भी है। इतना ही नहीं, एमसीआई और डीसीआई के चुनाव में सीधे तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे इस प्रकार की ग़लतियों को प्रश्रय मिल रहा है। ■

The Hindustan Times

LARGEST CIRCULATION IN NORTHERN, NORTH-WESTERN AND CENTRAL INDIA

KASHMIR ACCEDES TO INDIA

PLEBISCITE SOON ON RULER'S DECISION

Troops And Arms Flown To Srinagar

SHEIKH ABDULLA TO FORM INTERIM GOVT.

UNION TROOPS RUSHED FOR PROTECTION OF STATE

जम्मू-काश्मीर

...संवाद से ही भविष्य की राह मुमकिन

जुलाई 2016 में सत्याग्रह को समाप्त हुए 63 साल पूरे हो जायेंगे। वे मुद्दे, जिन्हें लेकर इस सत्याग्रह की शुरूआत हुई, उनमें से अधिकतर आज भी मौजूद है जिनका समाधान निकालना बाकी है। सवाल यही है कि आखिर क्यों न जम्मू-काश्मीर को लेकर जो नीतियाँ बनाई गई थीं, उनकी समीक्षा की जाये ? शेख अब्दुल्ला के 1947 से 1953 तक के शासन पर बारीकी से शोध किया जाये? इस राज्य को लेकर जितनी भी नीतियाँ बनी, उन्हें फिर से समग्र दृष्टि से देखा जाये?

■ देवेश खण्डेलवाल

जम्मू-काश्मीर के भारत में विलय के पश्चात् वहाँ क्रमागत विकास में भारतीय जनसंघ का विशेष योगदान रहा है। जम्मू-काश्मीर प्रजा परिषद् के साथ भारतीय जनसंघ ने 50 के दशक में वहाँ के लोगों के हित को ध्यान रखते हुए प्रजा परिषद् सत्याग्रह को समर्थन दिया था। यह सत्याग्रह वास्तव में जम्मू-काश्मीर के भविष्य के लिए अपेक्षाकृत सुधार लाने के लिए था। रामराज्य परिषद्, हिंदू महासभा और अकाली दल के साथ देशभर में अन्य कई विचारकों एवं राजनेताओं का इसे समर्थन प्राप्त था।

यह दुर्भाग्य था कि इस सत्याग्रह के दौरान 23 जून, 1953 को श्रीनगर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दुःखद निधन हो गया। लेकिन इसका दूसरा परिणाम यह भी निकलकर आया कि वहाँ राज्य और केंद्र- दोनों सरकारों की नीतियों पर विचार-विमर्श की शुरूआत हुई। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार था कि किसी ने जम्मू-काश्मीर के सन्दर्भ में दोनों सरकारों की नीतियों पर प्रश्न किये। इसके नतीजे निःसन्देह सकारात्मक थे। सत्याग्रह के बाद से वहाँ के नागरिकों को आंशिक रूप से ही सही, लेकिन मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति होने लगी और साथ ही भारतीय संविधान के अन्य कई प्रावधान लागू किये गए। लेकिन यह एक शुरूआती सफलता थी।

जुलाई 2016 में सत्याग्रह को समाप्त हुए 63 साल पूरे हो जायेंगे। वे मुद्दे, जिन्हें लेकर इस सत्याग्रह की शुरूआत हुई, उनमें से अधिकतर आज भी मौजूद हैं जिनका समाधान निकालना बाकी है। सवाल यही है कि आखिर क्यों न जम्मू-काश्मीर को लेकर जो नीतियाँ बनाई गई थीं, उनकी समीक्षा की जाये? शेख अब्दुल्ला के 1947 से 1953 तक के शासन पर बारीकी से शोध किया जाये? इस राज्य को लेकर जितनी भी नीतियाँ बनी, उन्हें फिर से समग्र दृष्टि से देखा जाये?

काश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर, 1947 को हुआ था। उस समय जम्मू-काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना वहाँ हमलावरों का मजबूती से सामना कर रही थी। उसी समय भारत सरकार ने 01 जनवरी, 1948 को इस युद्ध के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के समक्ष एक अपील की। यह अपील केवल भारतीय राज्य जम्मू-काश्मीर पर किए गए इस जबरन युद्ध को रोकने की मांग के सन्दर्भ में थी। सुरक्षा परिषद् में भारत की उचित मांग को नज़रअंदाज़ कर राज्य के विलय की पुनः चर्चा के साथ 13 अगस्त, 1948 को जनमत-संग्रह के प्रस्ताव को महत्ता दे दी गयी। भारत सरकार के लिए यह स्थिति अजीब हो गयी; क्योंकि जम्मू-काश्मीर के विलय के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता मांगी ही नहीं गई थी। वहाँ हुई इस गड़बड़ी को भारत सरकार ने स्वयं हल करने के लिए जम्मू-काश्मीर के लिए वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित एक पृथक् संविधान सभा के निर्माण का फैसला लिया किया। युवराज कर्ण सिंह ने 01 मई, 1951 को इस सन्दर्भ में घोषणा की।

इन चुनावों के साथ ही जम्मू-काश्मीर के भारत में विलय के चार साल हो चुके थे। इस दौरान राज्य की कमान शेख अब्दुल्ला के हाथों में रही। सबसे पहले 30 अक्टूबर, 1947 को उन्हें आपातकालीन प्रशासन का मुखिया बनाया गया। यह प्रशासन 5 मार्च, 1948 को भंग कर दिया गया और राज्य की पहली अंतरिम सरकार की बागडोर सँभालने का अधिकार शेख अब्दुल्ला को सौंपा गया। इसके बाद जम्मू-काश्मीर में पहले चुनाव अगस्त-सितम्बर 1951 में हुए थे। एक तरफ शेख अब्दुल्ला के नेतृत्ववाली नेशनल कांफ्रेंस थी। दूसरी ओर प्रजा परिषद् थी जिसकी नीतियों और मांगों को दिल्ली में भारतीय जनसंघ का समर्थन प्राप्त था।

अब प्रजा परिषद् के पास अवसर था कि जिस अलगाववाद और साम्प्रदायिकता के खिलाफ वह सार्वजनिक सत्याग्रह कर रही थी, उसे संविधान सभा में हिस्सेदारी लेकर रोका जाए। चुनावों की तारीख़ घोषित होते ही प्रजा परिषद् ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जान-बूझकर प्रजा परिषद् के तकरीबन सभी प्रत्याशियों के पर्चे खारिज़ कर दिए गए। मजबूरन प्रजा परिषद् को विरोध जताते हुए चुनावों का बहिष्कार करना पड़ा। इसी के साथ शेख अब्दुल्ला के नेतृत्ववाली नेशनल कांफ्रेंस को राज्य की सभी 75 सीटों पर निर्विरोध जीत मिल गयी। इस प्रकार 31 अक्टूबर, 1951 को राज्य की संविधान सभा का निर्माण हुआ। राज्य में पहली बार जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी संविधान सभा का गठन हुआ था। लेकिन उसमें नेशनल कांफ्रेंस के अलावा किसी अन्य दल की संख्या शून्य थी।

सामान्य स्थिति तो वह होती जब राज्य के लिए संविधान-निर्माण की प्रक्रिया में नेशनल कांफ्रेंस के साथ राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी प्रजा परिषद् को भी हिस्सा मिलता। खुद शेख अब्दुल्ला ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि अगर कोई मेरे विचारों का विरोध करेगा तो उसके लिए घाटी में कोई जगह नहीं है। अब्दुल्ला के लिए जम्मू-काश्मीर में अन्य किसी दल की उपस्थिति नामुमकिन थी।

जब भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ, तब 16 जून, 1949 को उसमें शेख अब्दुल्ला सहित अन्य तीन व्यक्ति जम्मू-काश्मीर की तरफ़ से हिस्सा बने थे। इस संविधान सभा में सिर्फ कॉंग्रेस के सदस्य न होकर हर प्रदेश, हर जाति और हर दल के प्रमुख व्यक्तियों को जगह दी गई थी। लेकिन जम्मू-काश्मीर में यह स्थिति विपरीत थी। वहाँ अन्य किसी दल को संविधान सभा

एनआईटी, श्रीनगर में 31 मार्च, 2016 को भारत विरोधी नारे लगाए गए। जब अन्य छात्रों ने इसका विरोध किया तो उनकी बेरहमी से पिटाई की गयी। इस शर्मनाक घटना के विरोध में देशभर से प्रतिक्रियाएँ आईं और राष्ट्रहितों को लेकर एक मज़बूत राय बनी।

में जगह ही नहीं मिलने दी गयी। इस राज्य की संविधान सभा का दायित्व था कि वह राज्य के विलय को भारत के साथ स्वीकृति प्रदान करे। मूलभूत अधिकार, नागरिकता, वित्तीय एकीकरण, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रधानता और पाकिस्तान अधिकृत ज़मीन की मुक्ति के सम्बन्ध में नीति निर्माण करे। लेकिन अफसोस इस पूरी प्रक्रिया में किसी अन्य विचार को स्थान ही नहीं मिला।

यह उन कारणों में से एक है जिनसे जम्मू-काश्मीर की स्थिति हमेशा आशंकाभरी बनी रही। शायद अब इस कमी को पूरा करने का एक अवसर मिला है। हालाँकि अब राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है। लेकिन वर्तमान भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के गठन से उस विचार को पहली बार मज़बूत स्थान मिला जिसकी शुरूआत डॉ. मुखर्जी ने की थी।

डॉ. मुखर्जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाकर उनके बलिदान के साथ समझौता किया है। यह एक भ्रामक तथ्य है। डॉ. मुखर्जी के लिए शेख अब्दुल्ला कभी परिहार्य नहीं रहे। उन्होंने 7 अगस्त, 1952 को संसद में कहा, हम एक मित्रतापूर्ण शैली में शेख अब्दुल्ला और अन्यों से मुलाकात कर उन्हें हमारे दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना चाहते हैं। इसी चर्चा में उन्होंने कहा था कि जब भी शेख अब्दुल्ला दिल्ली में हों तो सरकार को विपक्ष के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर एक प्रतिनिधि मण्डल बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक दृष्टिकोण द्वारा वहाँ की स्थिति पर समाधान निकाला जा सके। शेख अब्दुल्ला से उन्होंने शान्तिपूर्ण समाधान के लिए 10 अगस्त, 1952 को श्रीनगर में व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात की। अपनी आकस्मिक मृत्यु से पहले भी वह एक बार और शेख अब्दुल्ला से मिलकर चर्चा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 8 मई, 1953 को उन्हें एक टेलीग्राम भी भेजा।

यह स्पष्ट है कि डॉ. मुखर्जी की मृत्यु प्रजा परिषद् के सत्याग्रह को समर्थन के चलते ही हुई थी। उनका मानना था कि प्रजा परिषद् की मांगें राज्य के साथ देशहित में हैं। यदि इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह खुद परिषद् को सत्याग्रह वापस लेने की पहल का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी जम्मू-काश्मीर पर चर्चा करने के लिए समय मांगा। सरकार से उन्होंने निवेदन किया कि जम्मू-काश्मीर की स्थिति पर चर्चा के लिए एक गोलमेज सम्मलेन बुलाया जाये। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के साथ पत्राचार किया। जम्मू-काश्मीर की स्थिति पर संसद में हुई सभी चर्चाओं में हिस्सा लिया। देश भर में जागरुकता के लिए सार्वजनिक सभाएँ कीं और लेख भी लिखे। दुर्भाग्यवश, शान्तिपूर्वक समाधान की उनकी प्रत्येक बात और मांग– दोनों की ही अनदेखी कर दी गयी।

प्रजा परिषद् का विलय तो 1970 में भारतीय जनसंघ में हो गया। विदित है कि 6 अप्रैल, 1980 को भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार जनसंघ और भाजपा की जम्मू-काश्मीर को लेकर स्थिति समान है। वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है। जम्मू-काश्मीर राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम का अनुसरण कर रही है। इस गठबंधन में भाजपा की मौजूदगी से कम-से-कम इतनी अपेक्षा है कि एक संवाद की प्रक्रिया की शुरूआत होगी। जम्मू-काश्मीर में अलगाव, साम्प्रदायिकता, और कट्टरपंथ को लेकर देशभर में जागरूकता का माहौल बनेगा।

संवाद किस प्रकार से होगा, एक उदहारण हाल की एक घटना से सामने आता है। उत्तरी काश्मीर के हंदवाड़ा में 12

अप्रैल, 2016 को स्थानीय युवकों द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़खानी का घटना सामने आयी। इसके बाद यह आरोप लगा दिया गया कि छात्रा के साथ छेड़खानी सेना के किसी जवान द्वारा की गई थी। सेना ने इस घटना का एक वीडियो जारी किया जिसमें स्पष्ट नज़र आता है कि इस अप्रिय घटना के जिम्मेदार स्थानीय बदमाश ही थे। इसके अगले दिन राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर सहित अन्यों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने इस घटना से संबंधित मामला उठाया तो मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने रक्षा मंत्री को भरोसा दिलाया कि इस मामले की समयबद्ध जाँच कर दोषियों को सजा दी जाएगी। यह एक ऐतिहासिक पहल है। इससे पहले केंद्र सरकारों द्वारा जम्मू-काश्मीर की स्थिति पर आमतौर पर न तो जानकारी ली जाती थी और न ही इस प्रकार के जवाब की अपेक्षा होती थी।

एक घटना और है जिससे देशभर में जम्मू-काश्मीर की स्थिति को लेकर विचार-विमर्श की शुरूआत हुई है। एनआईटी, श्रीनगर में 31 मार्च, 2016 को भारत विरोधी नारे लगाए गए। जब अन्य छात्रों ने इसका विरोध किया तो उनकी बेरहमी से पिटाई की गयी। इस शर्मनाक घटना के विरोध में देशभर से प्रतिक्रियाएँ आईं और राष्ट्रहितों को लेकर एक मज़बूत राय बनी। आमतौर पर जम्मू-काश्मीर से इस प्रकार की ख़बरें सामने नहीं आती थीं। एक ज़माना तो ऐसा था कि वहाँ क्या हो रहा है, उसकी जानकारी सेंसर होकर देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचती थी।

जम्मू-काश्मीर को लेकर सबसे विवादित मुद्दा अनुच्छेद 370 है। भारत की संविधान सभा ने 17 अक्टूबर, 1948 को अनुच्छेद 370 को मंजूरी दे थी। इस समय तक हमारे संविधान के निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका था और संविधान सभा संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा की तैयारी कर रही थी। काँग्रेस द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने बिना किसी ख़ास विरोध के पास कर दिया था। इसका कारण था कि संविधान सभा के सभी सदस्यों को इस बात पर सहमत करवा लिया गया कि जम्मू-काश्मीर एक युद्धग्रस्त क्षेत्र है। ऐसे में वहाँ किसी अस्थाई कानून की मदद ली जाये जिससे वहाँ की असामान्य परिस्थितयों को संतुलित किया जा सके। वर्तमान में वहाँ अब युद्ध तो चल नहीं रहा है। क्यों न अब अनुच्छेद 370 पर विचार किया जाये? संभवतः इसे हटाने के लिए फिलहाल तो कोई संवैधानिक प्रयास न हो। लेकिन विचार किया जा सकता है कि यदि इससे फायदा है तो उसे बनाए रखने में किसी को आपत्ति नहीं होगी और यदि नुकसान है तो इसे निरस्त करना ही ठीक रहेगा।

डॉ. मुखर्जी के लिए शेख अब्दुल्ला कभी परिहार्य नहीं रहे। उन्होंने 7 अगस्त, 1952 को संसद में कहा, हम एक मित्रतापूर्ण शैली में शेख अब्दुल्ला और अन्यों से मुलाकात कर उन्हें हमारे दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना चाहते है। इसी चर्चा में उन्होंने कहा था कि जब भी शेख अब्दुल्ला दिल्ली में हो तो सरकार को विपक्ष के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर एक प्रतिनिधि मण्डल बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक दृष्टिकोण द्वारा वहाँ की स्थिति पर समाधान निकाला जा सके। शेख अब्दुल्ला से उन्होंने शान्तिपूर्ण समाधान के लिए 10 अगस्त, 1952 को श्रीनगर में व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात की। अपनी आकस्मिक मृत्यु से पहले भी वह एक बार और शेख अब्दुल्ला से मिलकर चर्चा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 8 मई, 1953 को उन्हें एक टेलीग्राम भी भेजा।

लेकिन विचार किया जा सकता है कि यदि इससे फायदा है तो उसे बनाए रखने में किसी को आपत्ति नहीं होगी और यदि नुकसान है तो इसे निरस्त करना ही ठीक रहेगा।

सही मायनों में देखा जाए तो वहाँ यह सरकार बनाने का यह प्रयोग डॉ. मुखर्जी सहित प्रेमनाथ डोगरा और उन सभी महापुरुषों के बलिदान को साकार कर सकता है जिन्होंने अपने जीवन का त्याग इसलिए किया जिससे कि वे राज्य की बेहतरी के लिए वहाँ की जनता को वह सब अधिकार दिलवा सकें जो जाति, धर्म और क्षेत्र के लिए समान हो। जिस अधूरेपन को वे पूरा न सके, आज उसे कानूनी एकरूपता और सरलता के साथ राज्य की जनता के बीच संवाद की सकारात्मक पहल से पूरा किया जा सकता है। ■

अभिनवगुप्त की प्रासंगिकता

■ अवनीश सिंह राजपूत

भारत की ज्ञान-परंपरा में आचार्य अभिनवगुप्त एवं काश्मीर की स्थिति को एक 'संगम-तीर्थ' के रूपक से बताया जा सकता है। जैसे काश्मीर (शारदा देश) संपूर्ण भारत का 'सर्वज्ञ पीठ' है, वैसे ही आचार्य अभिनवगुप्त संपूर्ण भारतवर्ष की सभी ज्ञानविधाओं एवं साधनों की परंपराओं के सर्वोपरि समाहृत आचार्य हैं। आचार्य अभिनवगुप्त अद्वैतागम एवं प्रत्यभिज्ञादर्शन के प्रतिनिधि-आचार्य तो हैं ही, साथ ही उनमें अनेक ज्ञान-विधाओं का भी समाहार है। भारतीय ज्ञान एवं साधना की अनेक धाराएँ अभिनवगुप्तपादाचार्य के विराट् व्यक्तित्व में आ मिलती हैं और एक सशक्त धारा के रूप में आगे चल पड़ती हैं।

अभिनवगुप्त अनेक शास्त्रों के विद्वान् थे और शैवशासन पर उनका विशेष अधिकार था। काश्मीर-नरेश ललितादित्य ने 740 ई. जब कान्यकुब्ज प्रदेश को जीतकर काश्मीर के अंतर्गत मिला लिया, तब उन्होंने अत्रिगुप्त से काश्मीर में चलकर निवास की प्रार्थना की। वितस्ता (झेलम) के तट पर भगवान् शितांशुमौलि (शिव) के मन्दिर के सम्मुख एक विशाल भवन अत्रिगुप्त के लिए निर्मित कराया गया। इसी यशस्वी कुल में अभिनवगुप्त का जन्म लगभग 200 वर्ष बाद हुआ। उनके पिता का नाम नरसिंहगुप्त तथा माता का नाम विमला था।

आचार्य अभिनवगुप्त को शेषावतार माना जाता है। शेषनाग ज्ञान-संस्कृति के रक्षक हैं। अभिनवगुप्त के टीकाकार आचार्य जयरथ ने उन्हें 'योगिनीभू' कहा है। इस रूप में तो वे स्वयं ही शिव के अवतार के रुप में प्रतिष्ठित हैं। आचार्य अभिनवगुप्त के ज्ञान की प्रामाणिकता इस संदर्भ में है कि उन्होंने अपने काल के मूर्धन्य आचार्यों-गुरुओं से ज्ञान की कई विधाओं में शिक्षा-दीक्षा ली थी। उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने नौ गुरुओं का सादर उल्लेख किया है। भारतवर्ष के किसी एक आचार्य में विविध ज्ञानविधाओं का समाहार मिलना दुर्लभ है। यही स्थिति शारदा क्षेत्र काश्मीर की भी है। इस अकेले क्षेत्र से जितने आचार्य हुए हैं, उतने देश के किसी अन्य क्षेत्र से नहीं हुए। जैसी गौरवशाली आचार्य अभिनवगुप्त की गुरु-परम्परा रही है, वैसी ही उनकी शिष्य-परंपरा भी है। उनके प्रमुख शिष्यों में क्षेमराज, क्षेमेन्द्र एवं मधुराजयोगी हैं। यही परंपरा सुभटदत्त (12वीं शताब्दी) जयरथ, शोभाकरगुप्त महेश्वरानन्द (12वीं शताब्दी), भास्करकण्ठ (18वीं शताब्दी) प्रभृति आचार्यों से होती हुई स्वामी लक्ष्मण जू तक आती है।

आचार्य ने जब महाप्रयाण किया, तब उनके 10 हज़ार शिष्य काश्मीर में थे। श्रीनगर के निकट स्थित भैरव गुफा में प्रवेश कर उन्होंने सशरीर महाप्रयाण किया। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है, स्वयं को विस्मृति के आवरणों से मुक्त कर स्वरूप को जानना, शिवोहं की प्रतीति। काश्मीर त्रिक अथवा प्रत्यभिज्ञा-जैसे दर्शन की पुण्यभूमि है। जिस महादेवगिरि के शिखरों पर अवतरित

आचार्य अभिनवगुप्त के ज्ञान की प्रामाणिकता इस संदर्भ में है कि उन्होंने अपने काल के मूर्धन्य आचार्यों-गुरुओं से ज्ञान की कई विधाओं में शिक्षा-दीक्षा ली थी। उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने नौ गुरुओं का सादर उल्लेख किया है। भारतवर्ष के किसी एक आचार्य में विविध ज्ञानविधाओं का समाहार मिलना दुर्लभ है।

होकर स्वयं भगवान् शिव ने आगमों का उपदेश किया, वे धवल शिखर संपूर्ण देश से आज भी अपनी प्रत्यभिज्ञा की आशा रखते ।

अभिनवगुप्त का अवदान :

अभिनवगुप्त मुख्यतः शैवमार्गी हैं। उन पर तंत्र चिन्तन का भी गहरा प्रभाव है। परंतु उनकी प्रमुख पहचान प्रत्यभिज्ञादर्शन ही है। उत्पल की ईश्वरप्रत्यभिज्ञा पर दो विस्तृत व्याख्याएँ तथा तंत्रालोक-जैसा बृहत् ग्रंथ देकर अभिनवगुप्त ने भारतीय दर्शन-जगत् को एक नयी ऊँचाई पर पहुँचा दिया। इसी प्रकार ध्वन्यालोकलोचन के तर्क भी नितांत अभिनव प्रतीत होते हैं। उत्पल ने प्रत्यभिज्ञाशास्त्र का प्रणयन तो लोकहितार्थ ही किया था, लेकिन जटिलता और सूत्रवत् शैली के कारण आम लोगों तक यह दर्शन नहीं पहुँच सका। अभिनवगुप्त ने अपनी विस्तृत तथा स्पष्ट व्याख्याओं के द्वारा उसे सामान्यजन तक पहुँचाने का प्रयास किया। अपनी विवृत्तिविमर्शिनी की रचना के पीछे उनका लक्ष्य उत्पलदेव के विचारों को उजागर करना मात्र रहा है। इस प्रकार अपने पूरे-के-पूरे क्रियाकाल में उन्होंने उत्पल के सिद्धान्तों का ही अनुसरण किया है तथा कहीं अपना सिद्धान्त जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। किन्तु इतना हम निःसंकोच कह सकते हैं कि प्रत्यभिज्ञाशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र के विषय में हम जो कुछ भी जानते हैं, उन सबका श्रेय उनकी विस्तृत व्याख्याओं को ही जाता है। सोमानन्द, उत्पल तथा भरतमुनि के ग्रंथों की शैली इतनी सूत्रात्मक एवं पाण्डित्यपूर्ण थी कि अभिनव की व्याख्याओं के बिना इन्हें समझना एक दुष्कर कार्य होता। अतः अपने पूर्वाचार्यों के प्रति श्रद्धालु तथा उनके विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजूद अभिनव ने भारतीय दर्शन की लोकानुभूतिपरक व्याख्या की, उसी के कारण यह दर्शन आम लोगों तक पहुँच सका। विभिन्न भारतीय दर्शनों के मध्य संपर्क स्थापित करानेवाली अवधारणाओं को गढ़ने तथा उनके संश्लेषण का श्रेय भी अभिनवगुप्त को जाता है।

अभिनवगुप्त का रचना-संसार :

आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने जीवन को केवल तीन महत् लक्ष्यों के लिए समर्पित कर दिया– शिवभक्ति, ग्रंथ-निर्माण एवं अध्यापन। बताया जाता है कि अभिनवगुप्त ने लगभग 42 पुस्तकें लिखीं थी। लेकिन आज उनमें से कई तो उपलब्ध ही नहीं हैं। कुछ अधूरी पाण्डुलिपियाँ भी मिली हैं। तंत्र और शैवदर्शन के बारे में उनके प्रमुख ग्रंथों में तंत्रालोक और लाघवी और बृहद्विमर्शिनी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। तंत्रालोक तंत्र और शैव साधना पर विश्वकोशीय आकार का विशाल ग्रंथ है। इसी विषय को कम शब्दों और सरल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने एक और छोटा ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा गया तंत्रसार। इसी वर्ग में परमार्थसार भी शामिल है। संक्षिप्त और बृहत् विमर्शनियाँ अपने गुरु उत्पलाचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका पर भाष्य है। इसके अतिरिक्त, कुल-परम्परा पर लिखी मालिनी-विजयावार्तिका और परात्रिंशिकाविवृत्ति उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। परात्रिंशिका- विवृत्ति वास्तव में रुद्रमालातंत्र के 36 पदों का भाष्य है। मालिनीविजयातंत्र पर उन्होंने एक पुस्तक श्रीपूर्वशास्त्र लिखी थी, लेकिन वह अब उपलब्ध नहीं है। उनकी आरम्भिक रचनाओं में बोधपंचदर्शिका और पूर्णपंचिका-जैसी पुस्तकों का उल्लेख है। इनमें दूसरी अब नहीं मिलती।

कई स्तोत्रों, जिनमें भैरवस्तोत्र सबसे प्रसिद्ध है, के अतिरिक्त उनकी तीन महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रत्यक्ष रूप से शैव दर्शन के बारे में नहीं हैं, यद्यपि उन पुस्तकों की रचना का उद्देश्य शैव दर्शन की दृष्टि से ही व्याख्या करना है। पहली रचना है भगवद्गीतार्थसंग्रह। इसमें अभिनवगुप्त ने गीता को विद्या और अविद्या के बीच संघर्ष के रूप में देखा है और यह निष्कर्ष निकाला है कि परम चैतन्य के साक्षात्कार पर ही मोह से मुक्ति मिल सकती है। अन्य दो रचनाएँ सौन्दर्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के बारे में हैं। पहली अभिनवभारती भरतमुनि की रचना पर अपनी टीका है तो दूसरी रचना लोचन नाम से आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक पर। इस वर्ग में अभिनवगुप्त ने एक और पुस्तक लिखी थी जो उनके गुरु भट्टतोत की एक रचना पर आधारित थी। लेकिन यह पुस्तक काव्यकौतुकविवर्ण उपलब्ध नहीं है। कुछ लेखकों ने कुछ और अनुपलब्ध पुस्तकों की सूची दी है जिनमें अनुभवनिवेदनम्, देहास्थदेवताचक्रस्तोत्र, परमार्थद्वादशिका-

विवर्ण आदि हैं।

आज भी प्रासंगिक हैं अभिनवगुप्त :

अभिनवगुप्त ऐसे प्रतिभावान् दार्शनिक और चिन्तक थे जिन्होंने अनेक दार्शनिक मान्यताओं और साधना-पद्धतियों का समन्वय करते हुए एक समग्र दर्शन प्रस्तुत किया, एक ऐसा दर्शन जिसने समाज को हज़ारों वर्ष से चली आ रही अतिरंजनाओं से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया जिनसे समाज तब प्रभावित था और आज भी किसी-न-किसी रूप में प्रभावित है। अभिनवगुप्त ने शिवमार्ग पर चलने के लिए ब्राह्मण और शूद्र को समान स्तर पर रखकर आह्वान किया। साधना के लिए ऊँच-नीच के बीच अन्तर समाप्त कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने संन्यासी और गृहस्थ के बीच का अन्तर ही समाप्त कर दिया। अभिनवगुप्त स्वयं जीवनभर संन्यासियों की तरह अविवाहित रहे, लेकिन अपने भक्तों के लिए घर-गृहस्थी से भागकर साधना करने की बाध्यता नहीं रखी।

अभिनवगुप्त महान् आचार्यों की परम्परा को एकदम से नकारने में विश्वास नहीं करते थे। महान् ग्रंथों को त्याज्य न मानकर अभिनवगुप्त ने उनकी अपनी प्रतिभा के बल पर नयी व्याख्याएँ कीं। प्राचीन शास्त्रों की उनकी परिभाषाएँ नयी परम्पराएँ बन गयीं। अभिनवगुप्त के युग में जैसी समस्याएँ और चुनौतियाँ समाज के सामने थीं, वैसी चुनौतियाँ बौद्धिक और भौतिक स्तर पर आज भी हमारे सामने हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि अभिनवगुप्त का दार्शनिक चिन्तन जैसा प्रासंगिक दसवीं शताब्दी के लिए था, वैसा ही प्रासंगिक इक्कीसवीं शताब्दी के लिए भी है।

यह प्रासंगिकता इस अर्थ में भी है कि आज जम्मू-काश्मीर के बारे में बहस और चिन्तन का विमर्श बदलने की आवश्यकता है। प्राचीन शारदाखण्ड भारत का ऐसा सांस्कृतिक केंद्र रहा है जिसका स्पन्दन देश के सुदूर प्रांत भी महसूस करते रहे हैं। इस सांस्कृतिक, बौद्धिक और दार्शनिक प्रयोगशाला के निर्माण में देश के हर क्षेत्र के मनीषियों और विद्वानों का योगदान रहा है, चाहे वे दक्षिण के केरल और कर्नाटक के हों या पूर्व में असम और बंगाल के, या फिर गंगा-यमुना की घाटियों से आए हों। इसी प्रकार देश का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ शारदाखण्ड की प्रतिभा प्रतिबिम्बित न हुई हो। जब अभिनवगुप्त प्रत्यभिज्ञा पर बल देते हैं तो वे जीव के अन्तर में विद्यमान शिव की पहचान की बात करते हैं लेकिन आज हमारे सामने जन-जन के मन में बसे विराट् राष्ट्र की प्रत्यभिज्ञा की बहुत बड़ी चुनौती है जिसका समाधान आचार्य अभिनवगुप्त के बताए मार्ग से ही संभव है। ■

"आचार्य अभिनवगुप्त एक उत्कृष्ट साधक, श्रेष्ठ दार्शनिक और शैवदर्शन के प्रतिनिधि-आचार्य थे। उनका दर्शन लोक, वेद और तंत्र— तीनों को स्पर्श करता है और विभिन्न मान्यताओं का सुन्दर समन्वय करता है। यह अकल्पनीय है कि एक सहस्राब्दी पूर्व कोई दर्शन का आचार्य एक ओर तंत्रालोक-जैसी कालजयी रचना देता है, वहीं भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की टीका भी लिखता है। लोकमान्यता है कि काश्मीर के महादेवगिरि के शिखरों पर अवतरित होकर स्वयं भगवान् शिव ने आगमों का उपदेश किया।"

—पद्मश्री डॉ. जवाहरलाल कौल
कार्यकारी अध्यक्ष, आचार्य अभिनवगुप्त सहस्राब्दी समारोह समिति

परिचर्चा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा

छात्रहित में केंद्र सरकार का सराहनीय कदम

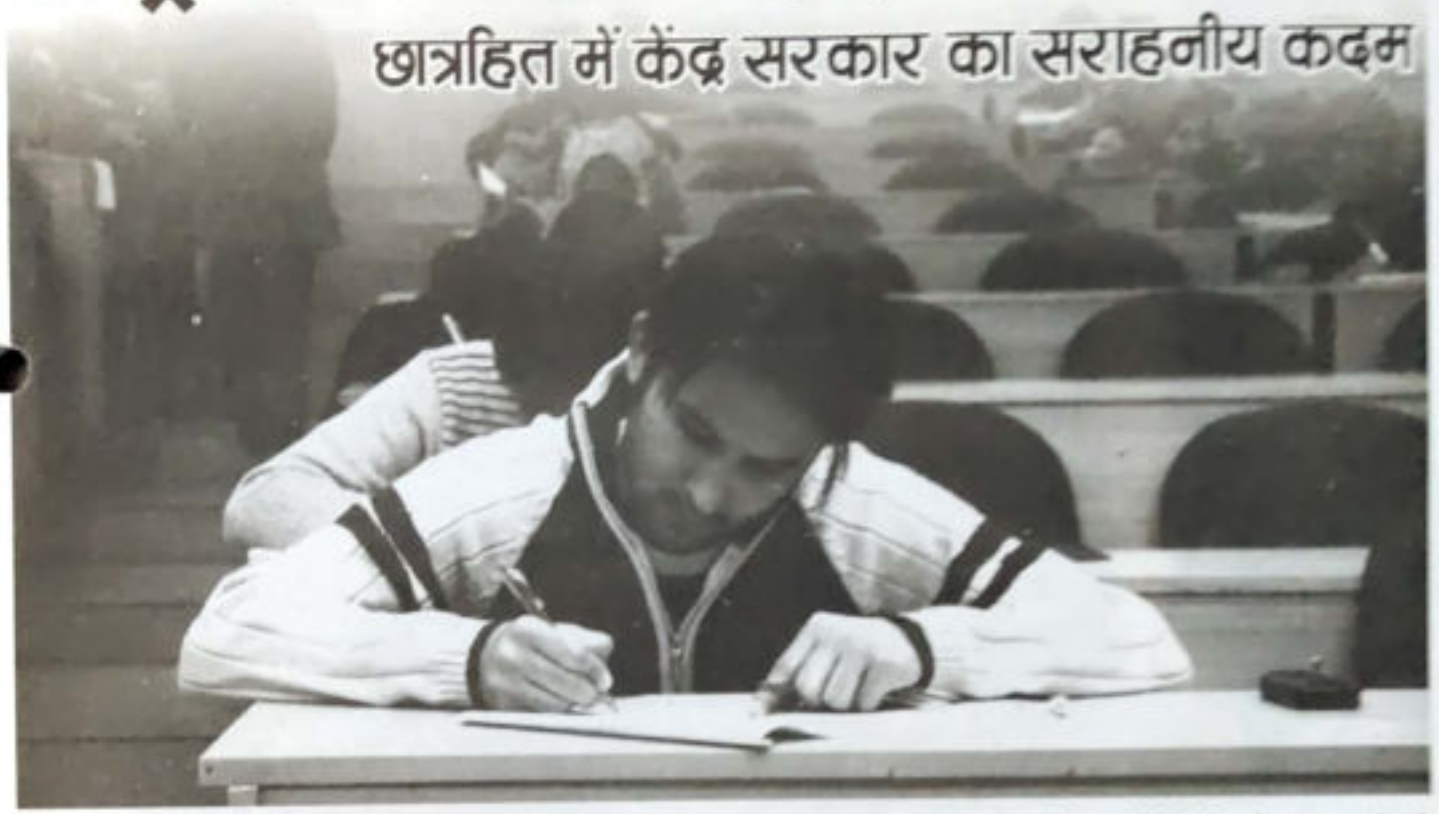

अभी तक देश में मेडिकल-पाठ्यक्रम में दाखिले के नाम पर अलग-अलग 90 परीक्षाएँ आयोजित होती थीं जिसके तहत छात्रों को सभी प्रवेश-परीक्षाओं के मद्देनज़र भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम की पढ़ाई भी करनी होती थी। ऐसे में विद्यार्थियों की समस्याओं को समझकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता-सह- प्रवेश परीक्षा (एनईईटी=नीट) आयोजित किए जाने का निर्णय लिया। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2017-'18 हेतु परास्नातक (पीजी) के लिए इस साल दिसंबर में होनेवाली प्रवेश-परीक्षा नीट के आधार पर होगी। सरकार ने इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सर्वोच्च न्यायालय का वह आदेश प्रभावी हो गया है जिसमें देश के सभी सरकारी, डीम्ड और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा 'नीट' को अनिवार्य करने का आदेश दिया था। फ़िलहाल इस साल राज्य सरकारों को नीट से बाहर रखा गया है, लेकिन निजी कॉलेजों की सीटें नीट के जरिए ही भरी जाएँगी। नीट के लागू होने को लेकर राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए **उत्कर्ष श्रीवास्तव** ने विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं से बात की।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है, वह किसी भी लिहाज़ से ठीक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश परीक्षा के ठीक पहले आने से छात्रों में असमंजस की स्थिति बन गई है। जो छात्र राज्य-स्तर की प्रवेश-परीक्षा पर ज़्यादा केन्द्रित थे, एकाएक नीट लागू होने से उनका भविष्य भी आधार में लटक रहा है। अतः केंद्र सरकार द्वारा नीट पर अध्यादेश लाकर पुनः परीक्षा करवाने का विकल्प पूर्ण रूप से छात्रों के हित में है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) करवाना बेहद ज़रूरी है और यह कई मायनों में सही भी है। केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश के अंतर्गत नीट की एकल परीक्षा हेतु एक वर्ष का समय मिलने से छात्रों को इसकी तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। आगामी वर्षों में मेडिकल के लिए केवल नीट (कॉमन एग्जाम) की ही परीक्षा हो– ऐसा सुनिश्चित किया जाना अति अवश्यक है। –**विवेक कुमार मौर्य (कोटा)**

परिचर्चा

नीट की परीक्षा को समान रूप से सभी राज्यों में लागू करके एक सामान्य प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन करने का सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला स्वागत योग्य है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब केवल एक ही पाठ्यक्रम पढ़ना होगा और स्वयं को उसपर केन्द्रित होकर तैयारी करनी होगी। मगर एक सवाल खड़ा हुआ है कि नीट के माध्यम को स्वीकार करनेवाले झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली-जैसे राज्य के छात्र मात्र दो महीनों में सीबीएसई का सिलेबस कैसे पूरा कर पाएँगे? ऐसे में इस वर्ष नीट लागू करने का फ़ैसला गैर-सीबीएसई छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। न्यायालय का निर्णय देर में आने से छात्रों का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को यह समझना भी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा के लिए तैयारी भी वैसी ही करनी होगी। राज्य सरकारों को भी अब अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव लाना होगा जिससे प्रत्येक राज्य के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर होनेवाली इस परीक्षा में बिना किसी समस्या (पाठ्यक्रम-संबंधी) के हिस्सा ले सकें। —प्रिया सिंह (इलाहाबाद)

जो छात्र इस वर्ष कठिन परिश्रम करके राज्य-स्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी किए हैं, उन्हें यदि किसी और की ग़लती (कोर्ट और एमसीआई) के कारण इस वर्ष परीक्षा से वंचित किया जाता है तो यह सरासर ग़लत है। ऐसे में इस वर्ष राज्यों को प्रवेश-परीक्षा का विकल्प देना सही निर्णय है। इससे एक ही पाठ्यक्रम में दाख़िले के लिए कई प्रवेश-परीक्षा देने से छात्रों को निज़ात मिलेगी और एक परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने में सहायता मिलेगी। एक कॉमन एग्ज़ाम होने से कई फॉर्म भरने के खर्च से भी छात्रों को राहत मिलेगी क्योंकि कोई भी मेडिकल प्रवेश-परीक्षा का शुल्क हज़ार रुपये से कम नहीं है। आज के समय में मेडिकल-प्रवेश के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। प्रायः किसी-न-किसी राज्य की मेडिकल प्रवेश-परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है और इस तरह के भ्रष्टाचार के कारण छात्र काफ़ी हतोत्साहित हो जाते हैं। मेडिकल की शुचिता और पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए और इस क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए नीट ही एकमात्र सही विकल्प नज़र आता है। —अक्षरा पी. कुमार (केरल)

नीट को केन्द्रीय परीक्षा के रूप में बहुत पहले ही सर्वमान्य घोषित कर देना चाहिए था, यह काम बहुत देर से हुआ। राज्यों के द्वारा ली जानेवाली मेडिकल और डेंटल प्रवेश-परीक्षाओं में बहुत-सी ख़ामियाँ हैं जिसके चलते प्रत्येक वर्ष छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। कभी प्रश्न-पत्र आउट हो जाता है तो कभी आरक्षित कोटे के चलते सामान्य छात्रों को दाख़िला नहीं मिल पाता। आए दिन निजी कॉलेजों की मनमानी के चलते मैनेज़मेंट की सीटें दबाकर डोनेशन से प्रवेश देने की ख़बरें सुनाई पड़ती हैं। राज्यों की मेडिकल प्रवेश-परीक्षा में धांधली की ख़बरें कोई नयी बात नहीं है, अतः नीट के चलते इस पर नकेल कसी जा सकेगी। एकीकृत परीक्षा के होने से आरक्षित छात्रों के अलावा सामान्य वर्ग के उन छात्रों को भी राहत मिलेगी जो किसी राज्य में अधिक आरक्षित कोटे के चलते मात्र कुछ अंकों से प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। —कुँवर रणंजय सिंह (वाराणसी)

एमबीबीएस और बीडीएस में राज्यों द्वारा प्रवेश-परीक्षा करवाना ठीक नहीं है। इसके लिए सामान्य प्रवेश-परीक्षा प्रणाली ही बेहतर तरीका है। प्रवेश के नाम पर गैर-सरकारी और डीम्ड कॉलेज अभिभावकों से 40-50 लाख रुपये डोनेशन लेकर किसी योग्य छात्र के भविष्य को बर्बाद करते हैं। वास्तव में राज्यों का पाठ्यक्रम और नीट का पाठ्यक्रम में काफ़ी अंतर है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का नीट को लागू करने का फ़ैसला छात्रों की समस्याओं को कम ही करेगा। नीट लागू होने के अचानक फ़ैसले के कारण जो छात्र इस वर्ष नीट (1 मई) की प्रथम परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए, उन्हें दोबारा परीक्षा का मौका देना सरकार के सही निर्णय को दर्शाता है। —अक्षत (कल्याण, महाराष्ट्र)

जम्मू में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव-क्रमांक 1
राष्ट्र-निर्माण व समाज-परिवर्तन का केन्द्र बनें विश्वविद्यालय

तक्षशिला, नालन्दा व विक्रमशिला-जैसे विश्वविद्यालयों ने एक समय भारत को विश्वगुरु का स्थान दिलाया था, ये विश्वविद्यालय तत्कालीन राष्ट्र, समाज एवं विश्व-मानवता की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले एवं दिशा देनेवाले प्रतिष्ठित केन्द्र थे। किन्तु आज भारत की विश्वविद्यालयीय शिक्षा एवं राष्ट्र व समाज की आवश्यकताओं के बीच तालमेल का स्पष्ट अभाव है। विश्वविद्यालयों का स्थानीय समस्याओं के समाधान से कोई सरोकार नहीं है।

आज देश के विश्वविद्यालय संशाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालय ज्ञान-नये प्रयोग-गुणवत्ता व धन की दृष्टि से कुपोषित हैं। प्रशासनिक अकुशलता एवं भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् का स्पष्ट मानना है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सामाजिक अनुभूति एवं राष्ट्रवाद जागृत करनेवाली विषयवस्तु शामिल की जाय तथा विश्वविद्यालय प्रशासन में व्यापक प्रशासनिक सुधार किए जायँ जिससे–

1. छात्र-छात्राओं में देश के मानबिन्दु, महापुरुषों एवं संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जागृत हो।
2. भारतीय अध्यात्मिक ज्ञान को भी पाठयक्रमों में जोड़ा जाए।
3. सामाजिक समरसता-पर्यावरण, लैंगिक समानता-जैसे मानवीय भाव छात्र-छात्राएँ धारण करें।
4. विश्वविद्यालय स्थानीय समाज की आवश्यकताओं व समस्याओं के समाधान का केन्द्र बनें।
5. सभी विश्वविद्यालयो में राष्ट्रध्वज फहराया जाए।
6. कला-संगीत-खेल व अन्य सामाजिक कार्यों में छात्र-छात्राओं की भागीदारी अनिवार्य हो जिससे युवाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके।
7. राष्ट्रवाद व सामाजिक अनुभूति हेतु पाठ्यक्रम आरम्भ हो।
8. देश के समक्ष उपस्थित आर्थिक-तकनीकी-सामरिक एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करनेवाले शोध-कार्य सुनिश्चित किए जायँ एवं विश्वविद्यालय नये सुझाव तथा नयी कल्पनाओं हेतु तकनीक विकसित करने का केन्द्र बनें।
9. 'भारतीय सीमा दर्शन'-जैसी परियोजना भी विश्वविद्यालयों में शामिल हो।
10. विश्वविद्यालय स्वरोजगार एवं कौशल-प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देनेवाले केन्द्र बनें।
11. विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय पहल करनेवाले केन्द्र बनें।
12. छात्रसंघों को सुदृढ़ कर उनकी रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित की जाए।
13. 'छात्र कल्याण निधि' का उपयोग समयबद्ध रूप से छात्रहित में किया जाय।
14. विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाएँ अपनी 'निगमित निधि' (कॉर्पस फण्ड) का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु विशिष्ट संस्थानों की स्थापना, संचालन तथा शोध-कार्य पर करें।

अ.भा.वि.प. की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र व राज्य सरकारों से मांग करती है कि वे विश्वविद्यालयों को राष्ट्र-निर्माण व सामाजिक परिवर्त्तन का केन्द्र बनाने की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएँ, साथ ही छात्र-छात्राओं का आह्वान करती है कि विश्वविद्यालयों को आधुनिक सन्दर्भ में समर्थ व सक्षम बनाने हेतु अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव-क्रमांक 2
शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए तत्काल केन्द्रीय कानून बने

इस वर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देशभर में मेडिकल के लिए एक ही प्रवेश-परीक्षा कराने का निर्देश दिया है जिसके निमित्त निजी संस्थानों में भी सरकार का नियंत्रण रहेगा। साथ ही भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को भी इस परीक्षा में शामिल किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करती है एवं सरकार से यह मांग करती है कि सम्पूर्ण शिक्षा में इसे लागू करना चाहिए।

वर्तमान समय में देश में अन्य व्यावसायिक शिक्षा-क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं व्यापारीकरण की वजह से हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उच्च शिक्षा के इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता वर्षों से अनुभव की जा रही है।

विगत दो दशकों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक निजीकरण के नाम पर, शिक्षा का घोर व्यापारीकरण हुआ है। देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन बढ़ाने के प्रयासों के बदले में निजी विश्वविद्यालयों तथा निजी शिक्षण-संस्थाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, परन्तु इन संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों से अत्यधिक शैक्षिक शुल्क व अन्य मदों के नाम पर अवैध वसूली कर उनका शोषण हो रहा है। समग्र केन्द्रीय कानून न होने के कारण शिक्षा में व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार व अराजकता में वृद्धि हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला एक अवसर है कि अब सरकार स्वयं पहल करके केन्द्रीय कानून बनाए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह संकल्प है कि जब तक केजी से लेकर पीजी तक अन्तिम विद्यार्थी को व्यापारीकरण मुक्त शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक उसका संघर्ष जारी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि शिक्षा में बढ़ रहे व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार व निजी विश्वविद्यालयों व अन्य निजी शैक्षणिक संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाते हुए शुल्क, सीट एवं आधारिक संरचना के नियंत्रण के लिए अविलम्ब व्यापक केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

प्रस्ताव-क्रमांक 3
परिसरों में देशद्रोही गतिविधियों से पुनः उजागर हुआ वामपंथ का असली चेहरा

विगत कुछ महीनों में देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों– जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय व जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथी तत्त्वों द्वारा की गई देशद्रोही गतिविधियों की विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् कड़ी निन्दा करती है और यथास्थान व यथाशक्ति उनका तीव्र प्रतिकार करने पर इन संस्थानों के राष्ट्रवादी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनन्दन करती है। इन विश्वविद्यालयों में वामपंथी छात्रसंगठनों द्वारा अफज़ल गुरु, मकबूल भट्ट और याकूब मेमन-जैसे आतंकवादियों के समर्थन में तथा भारतीय गणराज्य व न्यायपालिका के विरोध में नारेबाजी का राष्ट्रवादी विद्यार्थियों ने कड़ा विरोध किया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक उद्देश्य से छात्रों में देशभक्ति के भाव के संचरण हेतु सतत कार्यरत है। परिषद् का यह स्पष्ट मत है कि देश की एकता और अखण्डता पर कोई भी प्रहार संपूर्ण भारतीय समाज पर प्रहार है और उसका तीव्र प्रतिकार करना सभी देशभक्त नागरिकों का कर्तव्य है। देश की न्यायपालिका भारत के संविधान के अनुसार कार्य करती है। अफजल, याकूब और मकबूल-जैसे आतंकवादियों को मृत्युदण्ड एक लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात् दिया गया। इस पर प्रश्न खड़े करना भारत के संविधान एवं न्यायपालिका का अपमान है।

शैक्षणिक संस्थानों में हुई इन घटनाओं को सरकारों व समाज द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जेएनयू परिसर में हुई 9 फरवरी की घटना में सभी प्रमाण होने के बावजूद अभी तक मात्र 3 लोगों की गिरफ़्तारी हुई है तथा शेष दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। देश की एकता व अखण्डता पर प्रहार करनेवाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई कर भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकनी आवश्यक है और यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् सरकारों से इन पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग करती है।

शैक्षणिक संस्थानों में हो रही ऐसी घृणित घटनाओं के पीछे खड़े इनके बौद्धिक पालकों और पोषकों को भी बेनकाब कर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने से ही ऐसी घटनाएँ रोकी जा

सकती हैं। शैक्षणिक संस्थानों में प्राध्यापकों के रूप में बैठे इन सफेदपोश नक्सलियों द्वारा लगातार कुछ विद्यार्थियों की मति भ्रमित कर उन्हें देशविरोध की ओर मोड़ना अत्यंत गंभीर और चिन्ताजनक विषय है। इन प्राध्यापकों द्वारा परिसर को जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर बाँटकर समाज में तनाव पैदा करने के कुप्रयास भी किए जा रहे हैं। इस मामले में जेएनयू प्रशासन द्वारा देशद्रोही गतिविधि करनेवाले व देशद्रोह उजागर करनेवालों पर एक ही प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई करना न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है। परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र व राज्य सरकारों से ऐसे बौद्धिक आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है। साथ ही इस घटना के बाद कुछ दिन तक दोषी छात्र किस प्रकार महिला छात्रावास में छिपे रहे व किन्होंने उनकी सहायता की, बाहर से आए हुए छात्रों को किसने आमंत्रित किया, बिना अनुमति के भी यह कार्यक्रम किसके दबाव में आयोजित हुआ, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक विस्तृत पर समयबद्ध जांच से लेने की माँग अभाविप करती है। ऐसे संवेदनशील मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर इन पर नकेल कसने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हुई शोधछात्र रोहित वेमुला की मौत का सच देश के सामने आना चाहिए। इस पूरे प्रकरण की समयबद्ध जाँच की मांग परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोहराती है। इसी मामले में एसएफआई से इस्तीफा देनेवाले विश्वविद्यालय के छात्रसंघ सचिव द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर एक विस्तृत जाँच की मांग परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है।

इस पूरे घटनाक्रम में यह बात भी स्पष्ट हुई है कि इन परिसरों में देशद्रोही और उनके समर्थकों की संख्या कम है तथा राजनैतिक रूप से मौन प्रवृत्ति के विद्यार्थी व शिक्षकों की संख्या अधिक है। यह एक विचारधारा या समूह की नहीं अपितु देश की लड़ाई है। अतएव, विद्यार्थी परिषद् ऐसी मौन सज्जनशक्ति से राष्ट्रहित में देश की एकता व अखण्डता की रक्षा हेतु तथा संविधान की रक्षा के इस पावन आंदोलन में मुखर होने का आह्वान करती है।

मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इन प्रतिष्ठित परिसरों में वामपंथियों और अलगाववादियों द्वारा चलाए जा रहे इस देशद्रोही षड्यंत्र का सच जनता के सामने लाने का अभिनन्दनीय कार्य किया, वहीं इस घटनाक्रम में मीडिया के एक वर्ग ने जिस प्रकार देशद्रोहियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश की, उससे उनके चरित्र की सच्चाई उजागर हुई है।

इन सभी घटनाक्रमों से वामपंथियों की देशद्रोही मानसिकता पुनः देश के सामने उजागर हुई है। इतिहास गवाह है कि जब-जब इस देश पर संकट की घड़ी आई है, तब-तब ये देश के ही विरोध में खड़े हुए हैं। जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तब वामपंथी उन्हें 'तोजो का कुत्ता' कहकर अपमानित कर रहे थे। ये ही वामपंथी महात्मा गाँधी को 'बुर्जुआ' कहकर और रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 'बुर्जुआ' कवि कहकर उनका विरोध करते रहे। वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु-जैसे महान् स्वाधीनता सेनानियों का इन्होंने अतिवादी कहकर तिरस्कार किया। पूरे स्वतंत्रता संग्राम से गायब रहनेवाले वामपंथियों ने मुस्लिम लीग के साम्प्रदायिक विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन कर देश की अखंडता को भंग किया। आज़ादी के बाद 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर देश में साम्प्रदायिक माहौल बनाया। 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वामपंथियों ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि माओ की फौज भारत को पूँजीवादी सरकार से मुक्त करने आ रही है। 1974 में वामपंथियों ने जननेता जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल व फासीवादी कहकर गालियाँ दीं। विगत तीन दशकों से देश के विभिन्न भागों में फैलते माओवाद का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने विभिन्न सांगठनिक रूपों से वामपंथी समर्थन कर देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालयों में देशविरोध की नयी आग लगाकर ये वामपंथी ऐसे बौद्धिक आतंकवादी पैदा कर रहे हैं जो सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की प्रशंसा करने की बजाय उन पर जैसे-तैसे आरोप लगाते हैं और आतंकियों की मज़ार सजाते हैं।

यह भी एक गम्भीर व चिन्ता का विषय है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते व राष्ट्रवादी संगठनों का विरोध करते-करते काँग्रेस व कुछ क्षेत्रीय दल देश के ही विरोध में खड़े हो गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी राजनैतिक दलों से देश की एकता और अखण्डता से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय एकता के लिए एक स्वर में बोलकर राष्ट्रधर्म पालन करने का आह्वान करती है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् देश के हर नागरिक, विशेषकर युवाओं से इन संविधानविरोधी व राष्ट्रद्रोही बौद्धिक आतंकवादियों का यथास्थान विरोध कर इनके इन

घृणित कृत्यों का मुँहतोड़ जवाब देने का आह्वान करती है।

प्रस्ताव-क्रमांक 4
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रों के उत्थान एवं समाज-परिवर्तन में भूमिका हो सुनिश्चित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रों के उत्थान एवं उनकी समाज-परिवर्तन में भूमिका सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्यरत है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् गौरव महसूस कर रही हैं कि पूरे देश में अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं में पढ़ने की ललक लगातार बढ़ रही हैं और बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्रा शिक्षा के सभी विधाओं में आगे बढ़ रहे हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद्, अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं में उद्यमिता-विकास हेतु कौशल विकास के अंतर्गत बजट में किए गए 500 करोड़ के विशेष प्रावधान एवं प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए एक खुदरा स्टॉल आरक्षित करने का स्वागत करती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अपनी मांग के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को उद्योग हेतु कम ब्याज दर और बिना गारंटी के ऋण देने की योजना का भी स्वागत करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों को मिलनेवाली शोधवृत्ति में 16,000 से 25,000 की वृद्धि का स्वागत करती है। अनुसूचित जाति, भारत की आबादी का 16.6 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का 8.6 प्रतिशत है। सन् 1980 के दशक में उच्चतर-माध्यमिक में 12,00,000 अनुसूचित जातीय एवं 3 लाख जनजातीय विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व था, वह प्रतिनिधित्व अब बढ़कर 38,51,000 अनुसूचित जाति व 13,83,000 अनुसूचित जनजाति का हो गया है। उच्च शिक्षा में जहाँ नाममात्र के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व था, वह संख्या भी अब बढ़कर 36,37,000 अनुसूचित जाति एवं 13,15,000 हो गई है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् 1980 से अभी तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के उच्च शिक्षा में उनकी बढ़ती सहभागिता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से मांग करती है कि–

1. छात्र-संख्या के अनुपात में अनसुचित जाति एवं जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावासों की संख्या सुनिश्चित की जाएँ।
2. राष्ट्रीय शोधवृत्ति शोध कर रहे सभी अनसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को उपलब्ध कराई जाये।
3. कौशल विकास के अंतर्गत जनजातीय समुदाय के परंपरागत कौशलों को स्थान देते हुए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
4. देश के प्रत्येक जिले में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनेवाले छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
5. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संविधानसम्मत आरक्षण उपलब्ध कराया जाए।

...शेष पृष्ठ 29 पर

बिगड़ती क़ानून-व्यवस्था के ख़िलाफ़ अभाविप का प्रदर्शन

समस्तीपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की समस्तीपुर नगर इकाई के कार्यकर्ता ज़िले में बिगड़ती क़ानून-व्यवस्था को देखते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। इस दौरान छात्रों ने सरकार और प्रशासन के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। अभाविप कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर शहर में पत्रकार राजदेव रंजन के हत्यारों की गिरफ़्तारी, पटना में इंटर के छात्रों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई और गया में आदित्य सचदेवा हत्याकाण्ड के विरोध में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बिहार के महागठबंधन सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। इस मौके पर आयोजित प्रतिरोध सभा को सम्बोधित करते हुए अभाविप के छात्र नेता ने कहा कि देशभर में शराबमुक्त और संघमुक्त का ढिंढोरा पीटनेवाले बिहार के सुशासन बाबू पहले बिहार को अपराधमुक्त बनाएँ। छात्र-नेताओं ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को लोकतंत्र पर हमला बताया. ग़ौरतलब है कि बिहार में लगातार हो रही है हत्याओं के मद्देनज़र राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। सीवान में पत्रकार की हत्या की सीबी आई जाँच की मांग की जा रही है।

विश्वविद्यालयों में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के पीछे वामपंथ

विद्यार्थी परिषद् ने की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई नारेबाजी पर कार्रवाई की मांग

अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) तथा जादवपुर विश्वविद्यालय में विद्रोह के लिए वामपंथ के राष्ट्रविरोधी चेहरे को ज़िम्मेदार ठहराया है। ऐसे मामले भविष्य में किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में न हों, इसके लिए परिषद् ने केंद्र सरकार से राष्ट्रविरोधी तत्त्वों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन **'उजागर हुआ वामपंथ का छद्म चेहरा'** विषय पर बोलते हुए राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे ने कहा कि परिषद् हरसंभव प्रयास करती है कि राष्ट्र के विरोध में उठनेवाले स्वर को को दबाया जाए। इसका उदाहरण जेएनयू में भी देखने को मिला, जब विश्वविद्यालय के छात्र संघ नेता सौरभ शर्मा ने देश के ख़िलाफ़ नारे लगानेवालों का विरोध किया। परिषद् सदैव देश की अस्मिता और अखण्डता के लिए खड़ी होती रही है और यह क्रम आगे भी चलता रहेगा।

श्री बिदरे ने वर्तमान शिक्षा-नीति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कहा कि देश में सात दशक से कोई ठोस शिक्षा नीति नहीं है। ऐसे में परिषद् ने 21-सूत्रीय प्रस्ताव मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को सौंपने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि शिक्षा-नीति में अमूल-चूल परिवर्तन होने चाहिए जिससे युवाओं को देश और देश के लिए कार्य करनेवाले लोगों की जानकारी हो, न की विदेशी आक्रमणकारियों की। छात्रों को अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं।

वहीं, बैठक में परिषद् द्वारा दो प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि पहला प्रस्ताव **'पर्यावरण-संरक्षण : समय की ज़रूरत'** और दूसरा **'जेएनयू व जादवपुर विश्वविद्यालय के वामपंथ का राष्ट्रद्रोही चेहरा'** विषय पर रहा। प्रस्तावों में कहा गया कि पर्यावरण से हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार पर्यावरण-संरक्षण के लिए पुख़्ता नीति बनाए, साथ ही उसके अनुपालन के लिए कठोर फ़ैसले भी किए जाएँ।

कार्यकारिणी में देश के वर्तमान परिदृश्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहित कई विषयों पर भी चर्चा हुई। अभाविप द्वारा ग्रामीण अंचलों में चलाए जा रहे सामाजिक सर्वेक्षणों पर भी मंथन किया गया। अब तक छह राज्यों के पच्चीस हज़ार गाँवों और दो लाख परिवारों के बीच परिषद् के कार्यकर्ता गए। इस दौरान, कार्यकर्ताओं ने गाँवों में रहनेवाले लोगों की वास्तविक स्थिति का ज़ायज़ा लिया। ■

फ़िल्म-समीक्षा

'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम'

कमज़ोर पटकथावाली साहसी फ़िल्म

■ आशीष कुमार अंशु

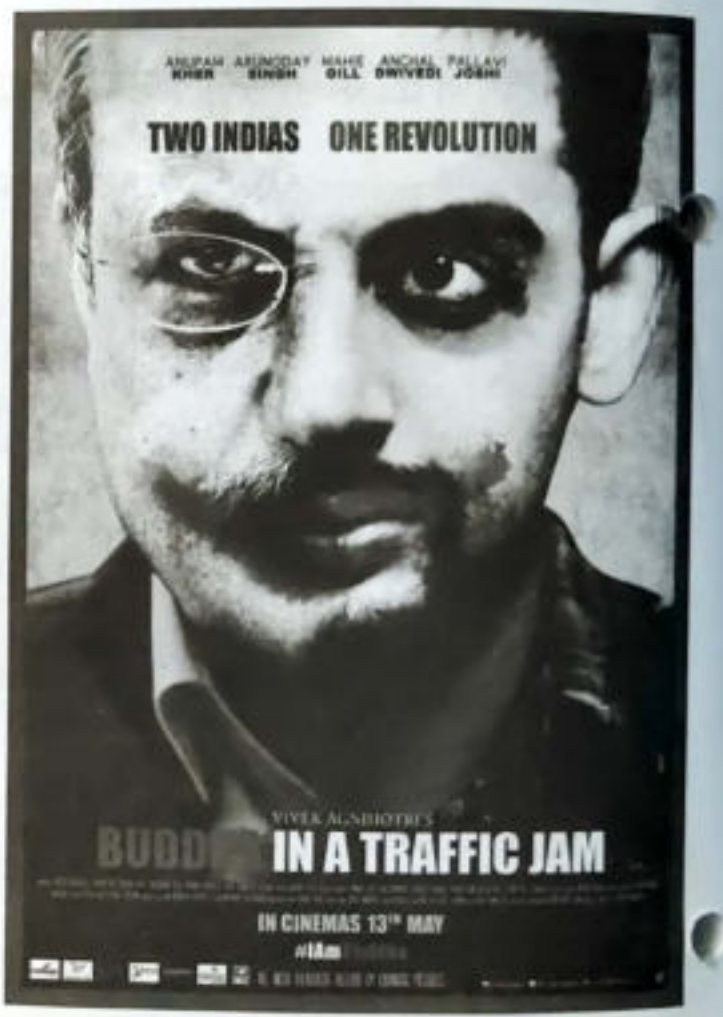

वर्ष 2014 की कहानी से फ़िल्म बस्तर से शुरू होती है, उसके 4014 साल पुराना एक दृश्य कुछ पलों के लिए पर्दे पर दिखलाई पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और फिर वर्ष 2014 के दूसरे दृश्य में भी कुछ नहीं बदला। एक व्यक्ति उसी तरह लकड़ी काट रहा होता है, जैसा 4014 साल पहले। इन हज़ारों सालों में कुछ भी तो नहीं बदला उन बस्तर के जंगलों में।

अनुपम खेर, अरुणोदय सिंह, पल्लवी जोशी, माही गिल के अभिनय से सजी विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्म **'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम'** आज के युवाओं को केन्द्र में रखकर बनाई गई है। इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग का विरोध जाधवपुर विश्वविद्यालय में हुआ। कथित तौर पर विरोध की वजह चुनाव आचारसंहिता थी। जबकि फ़िल्म में नक्सली और बुद्धिजीवी संबंध को जिस तरह रखा गया है, उससे जेएनयू और जाधवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध अपेक्षित था। फ़िल्म के एक संवाद के अनुसार नक्सली स्लीपर सेल हमारे आसपास कहीं भी हो सकते हैं। पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, छात्र, अभिनेता, गायक, थिएटर एक्टिविस्ट, एनजीओ, सीविल सोसायटी कहीं भी, किसी भी वेश में।

यह पूरी फ़िल्म कुछ किरदारों के आसपास रची गई है। प्रोफेसर रंजन पटकी, उनकी पत्नी शीतल, जो अपनी संस्था पॉटर क्लब के माध्यम से बस्तर के आदिवासियों द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के बर्तन को आदिवासियों से खरीदकर केन्द्र सरकार को बेचती हैं। उससे हुए मुनाफ़े को वह सामाजिक कार्यकर्ता चारु सिद्धू की एनजीओ को दान करती है। वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार नक्सली इलाकों में काम करनवाली एनजीओ के पैसों पर नकेल कसने का इरादा बनाती है। क्योंकि सरकार के पास इस बात की सूचना है कि नक्सलियों के पास आदिवासी क्षेत्रों में काम करनेवाले एनजीओ के माध्यम से भारी मात्रा में पैसा जा रहा है। सरकार द्वारा फंड रोकनेवाली नीति की जद में चारु सिद्धू की एनजीओ भी आ जाती है। शीतल के साथ मिट्टी के बर्तन खरीदने के करार को सरकार खत्म कर लेती है। इसके बावजूद शीतल हार नहीं मानती। वह तय करती है कि बस्तर के आदिवासियों के उस बर्तन को वह खुले बाजार में लेकर आएँगी, जो वे आदिवासी बुद्ध के समय से बना रहे हैं। इस काम में शीतल की मदद के लिए रंजन पटकी का एक छात्र विक्रम पंडित सामने आता है। विक्रम का पिंक ब्रा कैंपेन सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित रहा था। पिंक ब्रा को देखते हुए दर्शकों को

तहलका की पत्रकार निशा सुसन की याद ज़रूर आएगी।

विक्रम पंडित बस्तर के आदिवासियों के मिट्टी के बर्तन को बाज़ार में उतारने के लिए एक बेहतर योजना लेकर आता है जिससे सभी प्रभावित होते हैं। सिवाय प्रोफेसर रंजन पटकी के। प्रोफेसर, विक्रम की योजना को समर्थन क्यों नहीं देते, यह जानने के लिए आपको फ़िल्म देखनी होगी।

'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' अच्छे मकसद से तैयार की गई एक कमज़ोर फ़िल्म है जिसमें अख़बारी रिपोर्ट और सरकारी खुफिया सूचनाओं को पाठ्यक्रम के विभिन्न अभ्यासों की तरह अभ्यास एक, दो, तीन के खाँचे में बिठाकर पूरी कहानी को सपाट तरीके से कह दिया गया है। इस फ़िल्म की पटकथा के लिए किसी विशेष तरह का शोध किया गया हो, यह फ़िल्म देखकर नहीं लगता। यह फ़िल्म न आपको वैचारिक स्तर पर आंदोलित करती है और न ही फ़िल्म ख़त्म होने के बाद आपको घर तक ले जाने के लिए कोई संदेश देती है। फ़िल्म के नक्सली बनावटी जान पड़ते हैं। फ़िल्म के नक्सल-दृश्यों में गाँवों में खेली जानेवाली नौटंकी की याद आ जाती है। प्रोफेसर रंजन पटकी और विक्रम पंडित के बीच के संवाद सतही जान पड़ते हैं। जबकि इस संवाद को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता था।

कुछ विश्वविद्यालयों में ज़रूर इस फ़िल्म का विरोध हुआ क्योंकि अपनी कमज़ोर पटकथा के बावजूद यह फ़िल्म कुछ सच्चाइयों को उजागर करती है। जिसे पहले के फ़िल्मकार नहीं कर पाए। आजकल की व्यावसायिक फ़िल्मों के माहौल में इस तरह के साहस की अपेक्षा फ़िल्मों से समाज ने भी रखनी छोड़ दी है।

यह फ़िल्म का साहस ही है कि यह बता पाती है- हमें देश के बाहर के आतंकियों से अधिक ख़तरा देश के अंदर पल रहे देशद्रोहियों, देशविरोधियों, नक्सलियों से है। नक्सलियों को बड़ी संख्या में एनजीओ, पत्रकार, प्रोफेसर, छात्र, नेता, पुलिस, अधिकारी, कॉर्पोरेट की सहायता प्राप्त है। यह फ़िल्म माओत्से तुंग की इन पंक्तियों से ख़त्म होती है– 'रिवॉल्यूशन इज़ नॉट अ डिनर पार्टी।'

लेकिन नक्सलियों और उनके समर्थक छात्र और प्रोफेसरों को न माओत्से की यह पंक्ति याद है और न अवतार सिंह पाश का यह कहना– 'रात की चाँदनी में क्रांति की बात करनेवालो ! जिस दिन क्रांति आएगी, दिन में तारे दिखला देगी।' ■

बी. आर. आंबेडकर पुस्तकालय होगा जे. एन. यू. के पुस्तकालय का नाम

नयी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) की मांग पर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम बी. आर. अंबेडकर पुस्तकालय करने की सहमति दे दी है।

कैंपस में वामपंथी समूहों के साथ वैचारिक जंग में शामिल अभाविप ने अप्रैल में मांग की थी कि वहाँ भारतीय संविधान निर्माता की एक प्रतिमा भी लगाई जाए। जिस पर विश्वविद्यालय की पुस्तकालय कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विश्वविद्यालय का विधिक फैसला लेनेवाली कार्यकारिणी परिषद् के सामने रखा। परिषद् के एक सदस्य ने कहा कि प्रस्ताव को परिषद् के सामने रखा गया और केंद्रीय पुस्तकालय का नाम बी. आर. आंबेडकर पुस्तकालय करने पर सर्वसम्मति से मंजूरी दी गयी।

बता दें कि अभाविप ने महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी और मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर पुस्तकालय का नाम आंबेडकर के नाम पर करने के साथ सभागार ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के नाम पर और स्टेडियम ग्राउंड स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुण्डा के नाम पर रखने की मांग की थी। हालांकि परिषद् के सदस्यों ने दावा किया कि सभागार और स्टेडियम ग्राउंड के नाम के बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

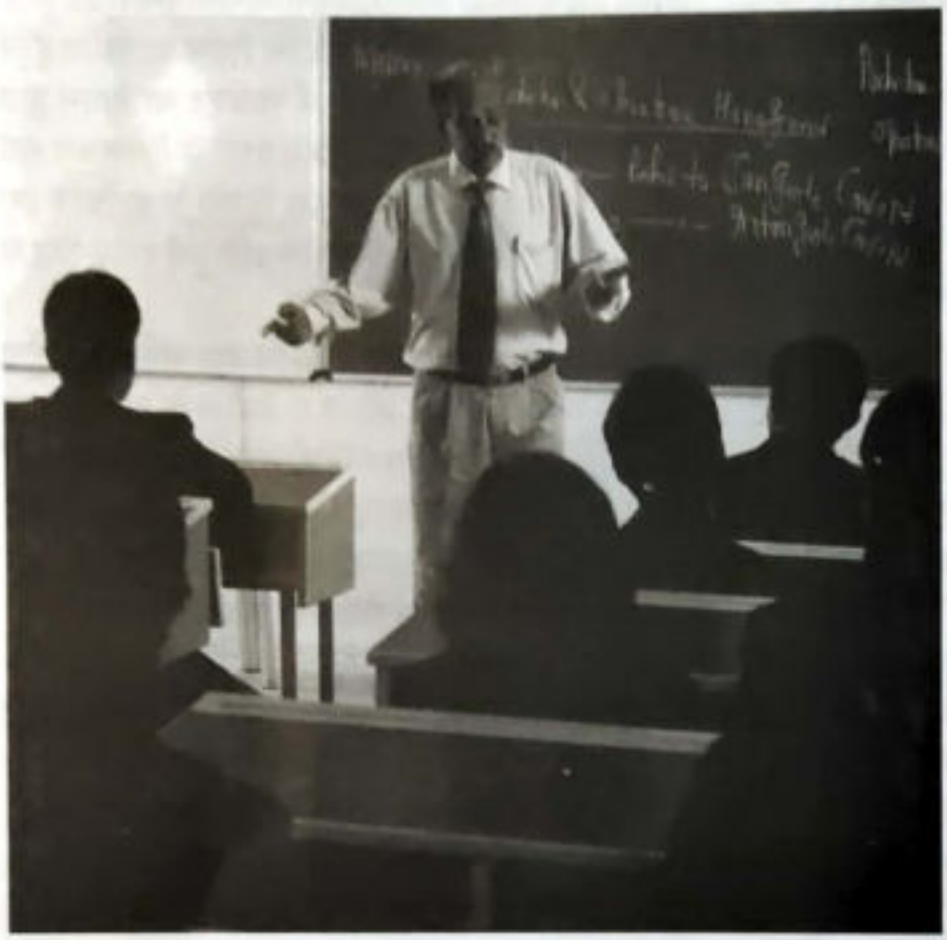

शिक्षा की स्वायत्तता

शैक्षिक स्वायत्तता का मतलब कुलपतियों, प्राचार्यों और शिक्षकों की निरंकुशता नहीं है। छात्रों की अराजकता भी नहीं है। स्वायत्तता सर्व-भागीदारी की अवधारणा पर आधारित विधिसम्मत सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया के प्रति एक निष्ठा है।

▪ संजय सत्यार्थी

शिक्षण का सरल शब्दकोशीय अर्थ है– सीखना और सिखाना। यह जीवनपर्यंत चलनेवाली प्रक्रिया है– पालने से अर्थी तक। एक व्यक्ति जीवन में कई शिक्षकों से सीखता है। एक शिक्षक अपने जीवनकाल में अनेक विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। मूलतः शिक्षण-कर्म शिक्षक और विद्यार्थी का आपसी मामला है। शिक्षण की प्रक्रिया तत्त्वतः स्वायत्त है। अर्थात् स्वायत्तता शिक्षण प्रक्रिया का मूल स्वभाव है, आवश्यक प्रतिष्ठान है।

क्या सीखना है, कितना सीखना है, कब सीखना है– यह विद्यार्थी की ज़रूरत, लगन और मेधा पर निर्भर करता है। क्या, कितना और कबतक सिखाना है– यह शिक्षक की योग्यता, समय और अभिप्रेरणा (मोटिवेशन) पर निर्भर है।

शिक्षण औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी। समय के साथ औपचारिक शिक्षण का व्याप बढ़ा है। शिक्षण का संस्थागत स्वरूप सुदृढ़ हुआ है। एक तय मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति होती है। वेतनभोगी शिक्षकों को निर्धारित पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाना पड़ता है। विद्यार्थी उपलब्ध पाठ्यक्रमों में चुनाव करता है, दाख़िला लेता है। वर्ष-दर-वर्ष पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, उत्तीर्ण होता है और आगे बढ़ जाता है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से निकलकर युवा-वर्ग अवसर और योग्यता के मुताबिक विभिन्न सामाजिक दायित्व वहन करता है, अपना भरण-पोषण करता है।

शिक्षण के संस्थानिक स्वरूप के विस्तार के कारण सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की स्वायत्तता बाधित हुई है। संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, प्रबंधकों का हस्तक्षेप बढ़ा है। यह सहज स्वाभाविक भी है। 'ही हू पेज दी पाइपर, प्लेज दी ट्यून' वाली कहावत हर क्षेत्र पर लागू है। हाँ, यह हस्तक्षेप उत्पात में न बदले, समर्थ लोगों को इसकी चिन्ता करनी चाहिये।

राजनीतिक व सामाजिक कारणों से सरकारी प्रबंधकों का जोर एडमिशन और बम्पर परीक्षाफल पर ज़्यादा रहता है, गुणवत्ता की बात पीछे रह जाती है। हाँ, यदा-कदा बनावटी रोष-प्रदर्शन चलता रहता है। दूसरी तरफ़ कुछेक धार्मिक-सामाजिक संगठनों द्वारा

संचालित संस्थानों को छोड़ दें, तो निजी संस्थानों के प्रबंधकों का ध्यान भी गुणवत्ता पर कम और मुनाफ़े पर अधिक रहता है।

अनुभव यह बताता है कि क्या, कितना और कबतक पढ़ना है– इसका निर्णय अब शिक्षक-विद्यार्थी के हाथ से निकलकर संस्थानिक प्रबंधकों के हाथ में सिमट गया है। सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्राचार्यों की स्थिति सचिवालय-मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहतर नहीं है। निजी संस्थानों में कुलपति और प्राचार्यों की हालत और भी दयनीय है। वे मात्र सजावट की वस्तु बनकर रह गए हैं, जिन्हें देखकर अभिजात्य वर्ग आकर्षित होता है। हर स्तर पर शैक्षणिक स्वायत्तता बाधित हुई है। लिहाज़वश, परम्परावश यदि कुछ स्वायत्तता बच रही थी, तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान (आर.यू.एस.ए.) के लागू होने पर इसके पूरी तरह समाप्त हो जाने का अंदेशा है। आशंका है कि आरयूएसए के तहत गठित उच्चस्तरीय मंत्रियों और अधिकारियों की समिति अब शोध और अभ्यासक्रम के विषय भी तय करेगी।

शैक्षणिक स्वायत्तता को अंदर शैक्षणिक जगत् से भी चुनौती है। लोकतंत्र में राजनैतिक दल और चुनाव एक सच्चाई है। चुनाव के लिए अधिक-से-अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने की होड़ लगी है। कई बार यह होड़ वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो जाती है। शिक्षकों के गुट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। परिणामस्वरूप स्वायत्तता अराजकता में बदल जाती है।

अभी हाल के दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) का घटनाक्रम इसका प्रमाण है जहाँ स्वायत्तता के नाम पर एक खास विचारधारा का वर्चस्व कायम करने का प्रयास हुआ। लम्बे समय तक शैक्षणिक वातावरण को अशांत रखा गया। छात्रों और शिक्षकों का एक समूह वर्ग-खण्ड की बजाय प्रशासनिक खण्ड के चबूतरे पर मजमा लगाता रहा। समाज में इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। शैक्षणिक स्वायत्तता का मतलब कुलपतियों, प्राचार्यों और शिक्षकों की निरंकुशता नहीं है। छात्रों की अराजकता भी नहीं है। स्वायत्तता सर्वभागीदारी की अवधारणा पर आधारित विधिसम्मत सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया के प्रति एक निष्ठा है।

उच्च शिक्षण के क्षेत्र में स्वायत्तता पर बाहरी और आंतरिक दबाव का परिणाम सामने है। गुणवत्ता में गंभीर गिरावट है। ज्ञानार्जन और लोक-व्यवहार– दोनों ही मोर्चों पर विफलता हाथ लगी है। प्रतिवर्ष लाखों ग्रेजुएट पैदा करनेवाले भारत में शोध और पेटेंट की स्थिति दयनीय है। कृषि, पशुपालन, उद्योग और सेवा– सभी क्षेत्रों में उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) निचले स्तर की है।

सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्राचार्यों की स्थिति सचिवालय-मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहतर नहीं है। निजी संस्थानों में कुलपति और प्राचार्यों की हालत और भी दयनीय है। वे मात्र सजावट की वस्तु बनकर रह गए हैं, जिन्हें देखकर अभिजात्य वर्ग आकर्षित होता है। हर स्तर पर शैक्षणिक स्वायत्तता बाधित हुई है।

सामाजिक व्यवहार के धरातल पर देश की स्थिति और भी खराब है। शिक्षा-संस्थानों में चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया प्रायः निष्पंद पड़ गई है। चौतरफ़ा बेईमानी, भ्रष्टाचार, चापलूसी और लापरवाही का बोलबाला है। उद्यमशीलता और व्यापारिक साहसिकता का अभाव है। शिक्षित युवा वर्ग में मायूसी है, आत्मविश्वास की कमी है। विज्ञान में पीएच. डी. युवा का ग्रुप सी और डी पदों के लिए आवेदन करना इसी ओर इशारा करता है।

शैक्षणिक गुणवत्ता में गिरावट को लेकर देशभर में चिन्ता है। खूब कोलाहल भी है। लेकिन वहाँ सन्नाटा पसरा है, जहाँ इसका समाधान है। कैम्पस और स्टाफ-रूम में इसे लेकर कोई हलचल नहीं है। राजनेताओं अधिकारियों और संस्थान-मालिकों के अँगूठे तले दबे शिक्षक तटस्थ और बेबस भाव से सबकुछ देख रहे हैं। कुछ मजे भी ले रहे हैं।

समाज-निर्माण के लिए उत्कृष्ट शिक्षण ज़रूरी है। उत्कृष्ट शिक्षण के लिए स्वायत्तता पर्याप्त शर्त भले ही न हो, पर है परम आवश्यक। बंगला चाहे सरकारी हो या निजी, गार्डन की सही देखभाल तो माली ही कर सकता है। समरथ लोगों को यह बात जितनी जल्द समझ में आये, उतना अच्छा। नयी शिक्षा नीति की सबलोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ■

दुराचार और हत्या की यह दिल दहला देनेवाली वारदात अकेली जीशा के साथ नहीं हुई है, यह केवल एक गरीब, मेहनती और महत्त्वाकांक्षी लड़की की अस्मिता और अरमानों का ही दमन नहीं है, बल्कि गुनहगारों ने उन हज़ारों-लाखों लड़कियों के अरमानों को भी बेरहमी से कुचला है, जो तमाम मुश्किल हालात के बावजूद कुछ कर गुजरने की न केवल चाह रखती हैं बल्कि चाहतों को अमली जामा पहनाने का हौसला भी रखती हैं।

कब तक मिलेगा केरल की निर्भया को इंसाफ़...?

■ वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा की अध्यक्षता में तैयार तथ्यान्वेषक दल की रिपोर्ट

केरल के एक गाँव की ग़रीब, मेहनती और वंचित वर्ग की युवती जीशा के साथ दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या दिल्ली के निर्भया काण्ड से कहीं ज़्यादा वीभत्स और दिल दहला देनेवाली वारदात है। निर्भया को दरिंदों ने तब शिकार बनाया, जब वह घर से बाहर थी। लेकिन जीशा तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह पाई। जीशा का कसूर बस इतना था कि वह ग़रीब, वंचित और दलित परिवार से थी। उसकी परित्यक्ता माँ राजेश्वरी ने कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को ऊँची शिक्षा दिलवायी। उसने कोट्टायम विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया और एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज से एलएल.बी. कर रही थी। यानी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने का कड़ा इरादा, कुछ कर दिखाने का हौसला और सपनों की ऊँची उड़ान। दुराचार और हत्या की यह दिल दहला देनेवाली वारदात अकेली जीशा के साथ नहीं हुई है, यह केवल एक ग़रीब, मेहनती और महत्त्वाकांक्षी लड़की की अस्मिता और अरमानों का ही दमन नहीं है, बल्कि गुनहगारों ने उन हज़ारों-लाखों लड़कियों के अरमानों को भी बेरहमी से कुचला है, जो

तमाम मुश्किल हालात के बावजूद कुछ कर गुजरने की न केवल चाह रखती हैं बल्कि चाहतों को अमली जामा पहनाने का हौसला भी रखती हैं।

जीशा की दिली इच्छा थी कि वह क़ानून की डिग्री लेकर समाज के उस वर्ग को इंसाफ़ दिलाए जो पिछड़ा है, वंचित है। जिसकी आवाज़ सत्ता की हनक और पैसे की खनक में दब कर रह जाती है, लेकिन शायद उसे सपने में भी यह एहसास नहीं था कि उसकी अपनी आवाज़ इतनी बेरहमी से दबा दी जायेगी।

जीआईए (ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एण्ड एकेड- मीशियंस) ने इस वीभत्स वारदात की सच्चाई का पता लगाने के लिए चार-सदस्यीय तथ्यान्वेषक दल का गठन किया। टीम ने मौका-ए-वारदात पर जाकर अनेक पहलुओं से मामले के तथ्य जुटाने की ईमानदार कोशिश की।

जीशा का घर एर्नाकुलम जिले के पेरूमबाबूर ताल्लुके के ग्रामीण इलाके की रायमंगलम् पंचायत में पड़ता है। यह इलाका ग्रामीण तो कहलाता है, लेकिन यहाँ झुग्गी-झोपड़ियाँ या आम गाँवों-जैसा माहौल नहीं है। जीशा के घर के आसपास खाते-पीते मध्यमवर्गीय लागों के बड़े और सुंदर मकान हैं। केवल जीशा की माँ का मकान ही एक कमरे का है, जिसमें न पीने का पानी है, न शौचालय और न ही स्नानघर।

हम आपको बताना चाहेंगे कि जीशा के पिता बहुत साल पहले अपनी पत्नी राजेश्वरी और दो बेटियों– जीशा और दीपा को छोड़कर इसलिए कहीं चले गये थे कि उनकी पत्नी बेटा पैदा नहीं कर सकी थी। बावजूद इसके राजेश्वरी देवी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत के बलबूते उसने बेटियों के पालन-पोषण और पढ़ा-लिखाई का ज़िम्मा ऊपर लिया। बड़ी बेटी दीपा ने दसवीं की पढ़ाई बीच में छोड़कर 16 वर्ष की उम्र में माँ को बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप घर छोड़कर चली गई। मां ने बेटी के नाबालिग होने का हवाला देते हुए कोर्ट में हैबियस कर्पस रिट दायर की, लेकिन बेटी घर नहीं लौटी। बड़ी बेटी से धोखा खाने के बाद मां ने छोटी बेटी जीशा पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। जीशा ने भी पढ़ाई-लिखाई में मन लगाया और एमए करने के बाद एलएल.बी. में दाख़िला ले लिया।

मृतका जीशा के घर के ठीक सामने एक संपन्न मध्यमवर्गीय परिवार रहता है नन्द कुमार और उनकी पत्नी श्रीजा। हमारी टीम ने इस परिवार से लंबी बातचीत की, ताकि कुछ पता चल सके। नन्द कुमार ने बताया कि उनका परिवार जीशा और उसकी माँ को लगभग 22 सालों से यहाँ देख रहा है। जीशा के घर में पीने के पानी का स्थाई इंतजाम नहीं था। श्रीजा ने बताया– 'जीशा बहुत अच्छी, मेहनती, खुशदिल और मिलनसार लड़की थी। जीशा ने बड़े सपने देख रखे थे। वह अपनी माँ को भी सारे सुख देने का इरादा रखती थी।'

दिनदहाड़े 28 अप्रैल को जिस तरह जीशा के घर में घुसकर उसकी अस्मत लूटी गई, निजी अंगों पर बेरहमी से प्रहार किए गए, आँतें बाहर निकाल दी गईं और चेहरे को हथौड़े से विकृत कर दिया गया, उससे पड़ोसी और गाँव के लोग सकते में हैं। उनका कहना है कि जीशा और उसकी माँ की किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसके साथ किसने और क्यों ऐसा किया, यह पड़ोसियों और आसपास के लोगों के लिए अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है।

जीशा बहुत अच्छी, मेहनती, खुशदिल और मिलनसार लड़की थी। जीशा ने बड़े सपने देख रखे थे। वह अपनी माँ को भी सारे सुख देने का इरादा रखती थी। दिनदहाड़े 28 अप्रैल को जिस तरह जीशा के घर में घुसकर उसकी अस्मत लूटी गई, निजी अंगों पर बेरहमी से प्रहार किए गए, आँतें बाहर निकाल दी गईं और चेहरे को हथौड़े से विकृत कर दिया गया, उससे पड़ोसी और गाँव के लोग सकते में हैं। उनका कहना है कि जीशा और उसकी माँ की किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसके साथ किसने और क्यों ऐसा किया, यह पड़ोसियों और आसपास के लोगों के लिए अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है।

केरल में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच किसी युवती के साथ ऐसी वीभत्स वारदात ने चुनावी रंग भी लिया। हमारी टीम के सदस्य रायमंगलम् पंचायत के वार्ड नंबर एक इराविचरा की पंच शीजा शाजी से बात की। शीजा ने बताया कि जीशा और उसकी माँ ज्यादातर किसी से बात नहीं करते थे। वे समाज से अलग-थलग रहते थे। हमने पंच शीजा से पूछा कि क्या किसी ने भी जीशा के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी ? तो उन्होंने बताया कि दिन ढल रहा था, आसपास के कुछ लोगों ने चीख-चिल्लाहट सुनी लेकिन उन्होंने सोचा कि माँ-बेटी के बीच कुछ कहा-सुनी हो रही होगी। मगर जब करीब सात बजे जीशा की माँ घर का दरवाजा खटखटाती रही और वह नहीं खुला तो उसने शोर मचाया। शोर सुनकर इकट्ठा हुए लोगों ने जब घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया तो दिल-दहला देनेवाला दृश्य देखकर सब सकते में आ गये।

पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और 4 मई को जीशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को जारी की गयी। इसमें बताया गया कि उसके साथ जघन्य वारदात दोपहर 1:30 से शाम 5:00 बजे के बीच की गई। उसके जननांग में धारदार हथियार से 30 गहरे वार किए गए। इसमें से एक जख्म तो 13 सेंटीमीटर तक गहरा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी या अपराधियों ने कितनी बर्बरता दिखाई। उसके सिर पर पीछे की ओर किसी कठोर वस्तु से वार भी किए गये। इतना ही नहीं, कपड़े से उसका दम भी घोटा गया।

अपनी बेटी का शव देख बेहोश होनेवाली माँ राजेश्वरी देवी की हालत अब भी ठीक नहीं है। फिलहाल उसके साथ उसकी बड़ी बेटी दीपा है जो माँ का ख़याल रख रही है। हमारी टीम जब अस्पताल में राजेश्वरी देवी से मिलने पहुँची तो राजेश्वरी ने हमारी टीम की अध्यक्ष एडवोकेट मोनिका अरोड़ा का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। भले ही हमारे बीच भाषा की दीवार हो, पर भावनाओं को समझने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उस पल राजेश्वरी की आँखों से बहते आँसू उसके दर्द को बयाँ कर रहे थे।

हमारी टीम में एक स्थानीय महिला साथी थी जो उनकी बातों का अनुवाद हमें बता रही थी। जिसके अनुसार, राजेश्वरी ने बताया कि जीशा को पिछले दो-तीन साल से धमकियाँ मिल रही थीं। उसे डराया-धमकाया जा रहा था कि वह क़ानून की पढ़ाई छोड़ दे। पुलिस को इस बाबत अर्ज़ी भी दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डबडबाई आँखों से एक माँ समाज, पुलिस, प्रशासन और नेताओं से सवाल कर रही है कि क्या कोई ग़रीब लड़की पढ़ नहीं सकती? क्या उसे जीने का हक़ नहीं है?

जीशा के साथ जघन्य वारदात और हत्या में पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह संदेह के घेरे में है। मीडिया ने अपनी रिपोर्ट और ख़बरों में इसके कई प्रमाण भी दिए। एक तौर पर मानें तो मीडिया ने ही जीशा हत्याकाण्ड मामले को जीवंत रखा, वर्ना पुलित ने तो इस पूरे मामले को आत्महत्या करार दिया था। एक समाचार-पत्र ने 'दलित क़ानून छात्रा की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या' शीर्षक से ख़बर चलाकर हलचल मचा दी थी जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस-अधिकारी, प्रशासन और नेताओं ने ज़वाब मांगने शुरू किए और जाँच का क्रम चला। मगर अब भी जीशा को इंसाफ़ नहीं मिल सका है। ■

देश जानने की अनोखी पहल

अनुभूति के बहाने कार्यकर्ता कर रहे समाज-दर्शन

अभिषेक रंजन

कार्यकर्ताओं को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व दैनिक समस्याओं से रूबरू होने के लिए विद्यार्थी परिषद् एक अनोखा अभियान चला रही है। सामाजिक 'अनुभूति' कार्यक्रम नाम के इस कार्यक्रम के जरिये देशवासियों के बीच अभाविप के हज़ारों कार्यकर्ता पहुँच रहे है। गाँवों में पहुँच लोगों से चर्चा कर रहे, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं और इस अनूठी पहल से समाज को देखने-समझने का एक ऐतिहासिक अवसर कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। देशभर में चल रहे इस कार्यक्रम की शुरूआत मई के प्रथम सप्ताह से हुई थी, जो अगस्त महीने तक चलेगी।

परिषद् के इस कार्यक्रम ने जनता का ध्यान तो खींचा ही, साथ ही सरकारी तंत्र के लिए भी एक सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। गाँवों में रात्रि विश्राम करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों से संवाद स्थापित करने और उनकी जीवनशैली का अध्ययन करने के दौरान छात्रों को एक नया अनुभव भी मिल रहा है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधि महज चुनाव के समय आते हैं। वोट मांगने और चुनाव जीतने के बाद आमजनों की बुनियादी समस्याओं के समाधान से उनका कोई मतलब नहीं होता है। अभाविप द्वारा चलाए जा रहे अनुभूति... शहर चला गाँव की ओर अभियान का असर सर्वेक्षण में शामिल विद्यार्थी कार्यकर्ताओं के मन-मष्तिष्क पर साफ़ देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने गाँव की जो तस्वीर देखी है उससे वे बेहद निराश हैं। उन्हें यह देखना बिल्कुल सहज नही लगा कि गाँवों में अभी भी शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली व यातायात आदि जनसमस्याएँ बदस्तूर कायम हैं। सिंचाई की कोई ठोस व्यवस्था के अभाव में खेती सही ढंग से नहीं हो पा रही है। रोज़गार के लिए ग्रामीण शहर की ओर पलायन करने को विवश हैं।

अभाविप कार्यकर्ताओं के सर्वेक्षण-दल ने अपने बेस कैम्प के जरिए लगभग आठ दिनों तक चिह्नित गाँवों में बिताया। सर्वेक्षण में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि आठ दिनों तक ग्रामीणों के साथ उठना-बैठना, खाना-पीना व साथ रहने से आत्मीय लगाव हो गया। उनलोगों का कहना था कि 'अतिथिदेवो भव' का सही अर्थ गाँवों में ही देखने को मिलता है। ग्रामीण भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हों लेकिन वे दिल से बहुत अमीर होते हैं। ग्रामीणों में इन कार्यकर्ताओं को देखने के बाद आशा की लौ जल उठी। लोगों को लगा कि उक्त कार्यकर्ता उनलोगों के दुःख को बाँटने के लिए आया है। अभाविप द्वारा चलाया गया यह कार्यक्रम वास्तव में अनोखा है। आनेवाले दिनों में इसका दूरगामी असर हो सकता है। लैपटॉप और मोबाइल से चिपके रहनेवाले आज की युवापीढ़ी के लिए यह काफ़ी प्रेरणादायी कार्यक्रम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनुभूति सर्वेक्षण-दल में ज़्यादातर शहर में रहनेवाले छात्र हैं, जो आजतक टेलीविजन और अखबारों के जरिए गाँव के बारे में जानते थे। वे आज गाँव में रहनेवाले परिवार के जनजीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। उनलोगों ने महसूस किया कि लाख परेशानियों में रहने के बावजूद ये लोग कैसे आपस में मिल-जुलकर हँसी-खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि शहरों में सारी सुविधा मौजुद होने के बावजूद लोग परेशान और तनावग्रस्त रहते हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं है। सब भागे जा रहे हैं। जबकि इसके विपरीत गाँववाले अपने यहाँ आनेवाले हर अतिथिओं को भगवान् स्वरूप मानते हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् झारखंड इकाई द्वारा अबतक 1,044 गाँवों का सर्वेक्षण किया गया। इस कार्य में 525 विस्तारक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। इस सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा कई जिलों में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के बारे में प्रदेश सह मंत्री सुनीता बेसरा ने बताया कि छात्रों का पलायन, महिला-उत्पीड़न, बाल मज़दूरी, कृषि और नशाखोरी समेत कुल दस बिंदुओं पर प्रश्नावली के साथ ग्रामीणों से चर्चा की गयी।

सामाजिक अनुभूति के तहत राजस्थान के 40 जिलों में 1,681 विस्तारकों द्वारा 2,169 गाँवों के 15,205 घरों में संपर्क करके वहाँ पर रहनेवाले लोगों के वास्तविक हालात का जायजा लिया गया। प्रदेश सह संगठन मंत्री मांगीलाल ने कहा कि सच भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। यदि 'अतिथिदेवो भव' क्या होता है, इसे देखना है तो लोगों को गाँवों में आकर देखना चाहिए। कार्यकर्ताओं का

सप्ताहभर कैसे गुजर गया, पता भी नहीं चला। वहाँ से लौटते वक्त गाँववालों का प्यार देखकर कार्यकर्ता काफ़ी भावुक हो गये। कार्यकर्ताओं का जत्था जब गाँवों में पहुँचा तो कार्यकताओं को एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। उन्हें लगा ही नहीं कि वे अपने घर से बाहर हैं। स्थानीय लोगों द्वारा अगाध प्रेम को देखकर अभाविप-कार्यकर्ता अभिभूत हो गये।

बिहार में भी अनुभूति कार्यक्रम 22 से 30 जून तक चला। 31 जिलों में 73 बेस कैम्प के जरिए कार्यकर्ताओं ने 1,296 गाँवों के 12,560 परिवारों से संपर्क किया। इस कार्य में 775 छात्र व 30 छात्राएँ संलग्न थीं। प्रान्त संगठन मंत्री श्री निखिल रंजन ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने जो स्थिति देखी है, वह बेहद निराशाजनक है। शिक्षा व स्वास्थ्य-सुविधाएं चौपट है, रोजगार नहीं मिल पा रहे, भ्रष्टाचार चहुँओर व्याप्त है। बिहार के पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों की सरकार चल रही है। ऐसे अनेक गाँव देखने को मिले जहाँ आजतक सरकारी मुलाजिम कभी नहीं पहुँचे। केन्द्रीय योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को पता नहीं, वही लोग अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा व रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिले अनुभव को साझा करते हुए श्री रंजन बताते हैं कि गाँव से लौटकर आये कार्यकर्ता काफी भावुक थे और गाँव की बदहाल स्थिति देख बेहद चिंतित। कार्यकर्ताओं की राय थी कि गाँव को केंद्रबिंदु बनाकर विकास का खाका खिंचा जाना चाहिए। सतत विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि गाँव भी विकास-यात्रा में सम्मिलित हों। साथ ही वे ऐसे आयोजन नियमित अंतराल पर किए जाते रहने के पक्ष में थे, ताकि कार्यकर्ताओं का ग्रामीण समाज से और जुड़ाव हो सके, उनके लिए कुछ कर सकें।

गुजरात में 262 कार्यकर्ताओं द्वारा 200 गाँवो में 7,240 घरों का सर्वेक्षण किया गया। विभिन्न गाँवों का दौरा करते समय कार्यकर्ताओं को तरह-तरह के अनुभव का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था। गाँव में रहनेवाले लोग स्वालंबी होते हैं। नदी-नालियों, खेतों-खलिहानों का वर्णन तो अभी तक ये लोग सिर्फ सिनेमाघरों में देखा करते थे। लेकिन आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो उसे देख-समझकर काफी रोमांचित हो उठे। हालांकि कभी-कभी इन गाँववासियों की ग़रीबी, लाचारी को देखकर दुःखी भी हो जाते थे। कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए अविस्मरणीय क्षण है। हमलोगों ने काफ़ी सुख भोग लिया। यदि हमलोग योग्य हुए तो हमें इन गाँववालों के लिए कुछ करना है।

छत्तीसगढ़ में भी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखने को मिल रहा था। जहाँ नक्सलियों के डर से सरकार भी जाने से कतराती है, वहाँ अभाविप कार्यकर्ता पहुँचकर सामाजिक अनुभूति के तहत घर-घर जाकर उनसे जुड़ने और उन्हें जानने का काम कर रहे थे। इस दौरान लोग अचंभित थे कि शहर में रहनेवाले ऐसे छात्र जो कभी बिना पंखे का नहीं रहे, वे भी सर्वेक्षण करने इस चिलचिलाती धूप में निकल पड़े है। कवर्धा में सामाजिक सर्वेक्षण संवेदना ग्राम दर्शन के लिए अभाविप-कार्यकर्ताओं की टोली को देखकर स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि 11 बजे से 3 बजे सूर्य की किरण झुलसा सकती है। घर से बाहर मत निकला करो। तब अभाविप-कार्यकर्ता ने बड़ी विनम्रता से ज़वाब दिया कि हमारे कई मित्र दोपहर के 12 बजे की प्रचण्ड गर्मी में भी अपने खेतों में काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ? अभाविप-कार्यकर्ताओं के इस उत्साह को देखकर डॉक्टर साहब काफी भावुक होकर बोले कि अब हमारे देश का भाग्य बदलनेवाला है। नदी-नालियों, जंगलों में गुजरते हुए छात्रों ने विभिन्न गाँवों में पहुँचकर वहाँ के लोगों का हाल-चाल जाना और रात्रि में विश्राम कर उनलोगों के दुःख-दर्द को जानने का प्रयास किया। गाँववालों के साथ भोज करना, रात में पीपल के पेड़ों के नीचे विश्राम करना कार्यकर्ताओं के लिए वास्तव में अपने आपमें एक अद्भुत पल था। गाँववालों को लगा कि शायद उनके लिए कोई मसीहा आया है। लेकिन उन्होंने जाना कि ये लोग कॉलेज़ में पढ़नेवाले छात्र हैं तो वे काफ़ी मायूस भी हुए। कायकर्ताओं ने कहा कि जब हमलोग गाँववालों से विदा ले रहे थे तो वे लोग काफ़ी भावुक हो गए थे। कुछ ही दिनों में हमलोगों का गाँववालों से भावनात्मक लगाव हो गया था। अपने हज़ार काम छोड़कर तपती दोपहर में रेगाखार और पांडा तराई के घोर जंगल के वनवासियों के घरों तक पहुँचकर उनकी जीवनशैली, रहन-सहन और आवश्यकता का अनुभव लिया।

उत्तरप्रदेश के 75 ज़िलों में 7,500 अनुभूति-कार्यकर्ताओं के 8,000 गाँवों में 1 लाख 75 हज़ार घरों में संपर्क कर उनका सर्वेक्षण करने का क्रम जारी है। काशी प्रान्त के संगठन मंत्री श्री आलोक पाण्डेय ने बताया कि अनुभूति के जरिये कार्यकर्ताओं को समाज को देखने की एक अलग दृष्टि मिली है। गाँव-गाँव जाकर लोगों से मिलने के क्रम में उन्हें वास्तविकता और किए जानेवाले कार्यों की समझ बनी है। आशा है, कार्यकर्ता समाज के इन वर्गों की बेहतरी के लिए अपने स्तर से भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। अनुभूति के बहाने उन्हें ज़रूर प्रेरणा मिली होगी।

आनेवाले दिनों में सभी प्रान्तों में अनुभूति-कार्यक्रम की एक समग्र रिपोर्ट आने के बाद देश की न केवल ज़मीनी सच्चाई देश, समाज के बीच परिषद् ले जायेगी बल्कि किए जानेवाले आवश्यक करणीय कार्यों के लिए सरकार तक भी अपनी बात पहुँचाएगी। अनुभूति के जरिये एक बेहद सटीक, व्यावहारिक व विस्तृत जानकारी इकठ्ठा हो रही है, जिससे देश की कई ज्वलंत समस्याओं, जैसे– सुरक्षा, धर्मांतरण, ग़रीबी, अशिक्षा को समझने व इनके निदान हेतु भी परिषद् प्रयास करेगी। ■

एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़े– इस प्रकार की नीतियाँ, कार्यक्रमों तथा खेल-प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य सरकार करे, जिससे सभी क्षेत्रों के बीच समन्वय, आपसी सौहार्द्र प्रस्थापित हो। साथ ही भौगोलिक दूरियों को कम करने की दृष्टि से सड़क, रेलगाड़ियाँ और अतिरिक्त विमानों की व्यवस्था की जाए।

कश्मीर के कुछ हिस्सों में जिस प्रकार से युवाओं को अलगाववाद की भाषा बोलकर भारत के खिलाफ उकसाया जा रहा है, उसी समय कुछ हिस्सों में यह भी ध्यान में आ रहा है कि अलगवादियों द्वारा बंद का आह्वान करने पर बंद को न मानना तथा उपमुख्यमंत्री द्वारा आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में आकर समस्याओं को रखना यह दर्शाता है की घाटी के लोग राजनैतिक सक्रियता के साथ-साथ अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं। साथ ही वर्षों से जम्मू व कश्मीर में बंद पड़े संवाद को पुनः बहाल करने की दिशा में सकारात्मक पहल करते दिख रहे हैं। घाटी के युवा भी अन्य प्रांतों की तरह शान्ति और समृद्धि के मार्ग पर चलना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक समस्त युवाओं से आह्वान करती है कि प्रदेश की शिक्षा, सुरक्षा, समृद्धि के लिए आगे आएँ और जम्मू कश्मीर के प्रगति के भागीदार बनें।

प्रस्ताव-क्रमांक 6
चिकित्सा-शिक्षा की अनियमितता को दूर करे सरकार

किसी भी स्वस्थ राष्ट्र के लिए योग्य चिकित्सा-पद्धति व चिकित्सक की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चिकित्सा-शिक्षा की नींव मजबूत होना सफल और सुलभ चिकित्सा के लिए अनवार्य है। किन्तु भारतीय चिकित्सा परिषद् (मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया), भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् (डेंटल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया) और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इण्डियन मेडिसीनिया) में बड़े पैमाने पर व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण भारत में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चिन्ताजनक बन गई है।

देश के अधिकाश मेडिकल कॉलेज शिक्षकों के अभाव और आधुनिक एवं स्तरीय चिकित्सा-शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसंरचना की कमी से ग्रस्त है। अधिकांश निजी मेडिकल कॉलेज अधिकतर मानकों को पूरा नहीं करते। कमोबेश यही स्थिति डेंटल कॉलेजों की भी है।

वस्तुतः देश में चिकित्सा-शिक्षा की बदहाल स्थिति का मुख्य कारण एमसीआई और डीसीआई द्वारा समय-समय पर निरीक्षण न किया जाना तथा मानकों का कड़ाई से पालन न कराया जाना है। निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने पर एमसीआई और डीसीआई द्वारा बड़े पैमाने पर किया जानेवाला भ्रष्टाचार आज आम चर्चा का विषय है।

एमसीआई और डीसीआई राजनीति का अखाड़ा बन चुके हैं। इनके चुनावों में धनबल और राजनीतिज्ञों से साँठ-गाँठ प्रभावी भूमिका निभाती है।

मेडिकल एवं दन्त चिकित्सा के शिक्षा में सुधार हेतु अभाविप की रा.का.प. बैठक एमसीआई और डीसीआई में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता महसूस करती है तथा केन्द्र सरकार से यह माँग करती है कि एमसीआई और डीसीआई का पुनर्गठन किया जाय एवं संसदीय समिति (पार्लियामेन्ट्री कमिटी) द्वारा दिए गए सुझाव का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाय।

प्रस्ताव-क्रमांक 7
पर्यावरण-संरक्षण के लिए संकल्पित हों युवा

हमारे पर्यावरण तंत्र में किसी भी भाग में यदि कोई असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण तंत्र पर दिखाई देता है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् वर्तमान पर्यावरण-असंतुलन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।

अभाविप ने पर्यावरण की समस्या को समझते हुए विकासार्थ विद्यार्थी के माध्यम से वृक्षारोपण, बंगलूरू में तालाब-संरक्षण, मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी को प्रदूषणमुक्त व सिंहस्थ कुम्भ को पॉलीथीनमुक्त रखने का संकल्प, उत्तरप्रदेश में गंगा नदी व घाटों की स्वच्छता अभियान व आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र में जल-संरक्षण का विशेष अभियान चलाया है। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् पर्यावरण कुम्भ (उज्जैन) में पर्यावरण-संरक्षण पर दिए गए बिंदुओं का अखाड़ा

परिषद् एवं संत समाज द्वारा दिए समर्थन का स्वागत करती है।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और युवा वर्ग का आह्वान करती है कि जल, जंगल, ज़मीन व वायु को बचाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान लेकर 'ग्रीन कैम्पस एण्ड क्लीन कैम्पस' की ओर अग्रसर हों, साथ ही पर्यावरण-संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संकल्पित होकर निम्न बातों की ओर अग्रसर हों–

1. प्रत्येक प्रांत जलवायु अनुकूल वृक्षारोपण कर उसका ध्यान रखे।
2. प्रत्येक विश्वविद्यालय व बड़े शैक्षिक संस्थानों के परिसर में सौर ऊर्जा का प्रयोग व वर्षा-जल का संचयन किया जाए।
3. प्रदूषणमुक्त अभियान के लिए सप्ताह में एक दिन मोटर वाहनों का प्रयोग न करें व सार्वजनिक सेवा परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दें।
4. गंगा किनारे के प्रदेश गंगा नदी व घाटों की स्वच्छता के लिए कार्ययोजना बनाकर नियमित प्रयास करें।
5. जलस्रोतों व जल-संरक्षण की कार्य योजना बनाकर पूरे देश में युवाओं द्वारा प्रयास किया जाए।
6. प्रत्येक विद्यार्थी पॉलीथीन का प्रयोग न कर विकल्प में पर्यावरण हितकारी सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करें।

अभाविप का स्पष्ट मत है कि उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर केंद्र व राज्य सरकारें ठोस एवं उपयोगी नीति बनाकर कार्यान्वित करे। समाज में व्यक्तिगत जीवन के संतुलन से पर्यावरण-संतुलन और लोगों में भारतीय संस्कृति आधारित जीवन-पद्धति प्रतिपादन होने से उनके मन में पर्यावरण-संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के प्रति श्रद्धा विकसित हो सकेगी। ■

अभाविप ने किया टॉपरों को सम्मानित

चंदवा (लातेहार)। 'चंदवा की बेटी काजल ने मैट्रिक की परीक्षा में झारखंड में सातवाँ स्थान लाकर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। वहीं इंटर साइंस में गरीब परिवार के विशाल सिंह ने जिले में पहला स्थान लाकर शहर का मान बढ़ाया है। इन छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से इसे साकार भी किया है'– उक्त बातें जिला परिषद् सदस्य अनिता देवी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् व करियर हाइट्स के संयुक्त तत्त्वाधान में आयोजित छात्र सम्मान समारोह में कही। बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करनेवाले छात्रों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर सतत प्रयास करने की बात करते हुए अनिता देवी ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार ज़रूरी है। बच्चों को अपने संस्कारों का भी ध्यान रखना होगा जिसके बलबूते वे अपने क्षेत्र की पहचान पूरे प्रदेश व देश को करा सकेंगे।

वहीं, प्रमुख नवाहीर उराँव व उपप्रमुख फिरोज़ अहमद ने बच्चों को मेहनत व लगन के साथ पढ़ाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक अच्छा नागरिक होना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जिसमें शिक्षकों व अभिभावकों को भी बच्चों के विकास में सहायक होने की बात कही। इस दौरान उपप्रमुख ने इस प्रकार के आयोजन के लिए अभाविप का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

बता दें कि इस सम्मान-समारोह में मैट्रिक में झारखंड की सातवीं सह जिला टॉपर काजल कुमारी के अलावा श्वेता कुमारी, पीयूष झा, इंटर विज्ञान जिला टॉपर विशाल कुमार सिंह, ऋतिक कुमार, कॉमर्स टॉपर प्रिंस कुमार, सुधा कुमारी व गुलशन के अलावा आईटीआई मेन्स में क्र वालीफाई करनेवाले सत्यम् कुमार को सम्मानित किया गया।

प्रिय मित्रो !

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का जून-जुलाई संयुक्तांक 2016 आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा खबरों का संकलन किया गया है। आशा है, यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें।

छात्रशक्ति भवन, 26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नयी दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
Visit us at : www.abvp.org
chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/chhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

मंज़िलें और भी हैं...

■ अजीत कुमार सिंह

जीवन का सबसे अहम पड़ाव होता है, किशोरावस्था। यह वह पड़ाव है जहाँ से हम अपने भविष्य को लेकर चिन्ता करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में हमारे अंदर असीम ऊर्जा का भंडार होता है। कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), आसीएसई तथा लगभग सभी राज्यों के 10वीं/12वीं के परीक्षा-परिणाम आ चुके हैं। 12वीं तक छात्रों को अपने भविष्य को लेकर कोई खास माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। पहले की अपेक्षा आजकल के छात्र अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सजग हो गए हैं। परीक्षा-परिणाम आते ही सभी छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोचना शुरू कर दिए होंगे।

शिक्षा के व्यावसायीकरण के इस दौर में मध्यम व निम्न आयवाले अभिभावक इतने लाचार हो चुके हैं कि लाख चाहने के बावजूद अपने बच्चों को बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। प्रतिभावान् छात्र भी अपने घर की माली हालत को देखते हुए मन मारकर बैठ जाते हैं। इन बच्चों के भविष्य के पंख उगने से पहले ही कुतर दिए जाते हैं। कई बार इस देश की प्रतिभाओं को सड़क पर धूल फाँकते देखा गया है।

बारहवीं का परीक्षा-परिणाम आते ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन-प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सभी छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय-जैसे नामी संस्थानों में दाख़िला मिलना संभव नहीं है। नामी विश्वविद्यालयों में 'कट-ऑफ' कभी-कभी सौ फीसदी तक चली जाती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए छात्र इस हाई 'कट-ऑफ' में कहीं टिक नहीं पाते और अपने-आपको असहाय पाते हैं। उसकी प्रतिभा कुण्ठित हो जाती है। अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाख़िला लेना तो उनके लिए 'आसमान में तारे गिनने के सामान' है; क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शुल्क के नाम पर मोटी धन उगाही का धंधा जो चल पड़ा है। साथ ही दाख़िला लेने से पहले डोनेशन के नाम पर 'मोटी रकम' चुकानी पड़ती है, जो उनके वश की बात नहीं है। इन सब परेशानियों से घबराकर ज़्यादातर छात्र अपने-आप में समझौता कर लेते हैं और किस्मत का फ़ैसला मानकर बैठ जाते हैं। ऐसे छात्र जो बढ़ते कट-ऑफ़ और महंगी फ़ीस के चलते दाख़िला नहीं ले पाए हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है; क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है– मंज़िलें और भी हैं...। ऐसे छात्र ज़ानकारी के अभाव में मन मारकर बैठ जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनके भविष्य के लिए कितने संभवनाओं के द्वार खुले पड़े हैं।

वर्तमान समय में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के द्वारा कई ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो वंचित छात्रों के लिए अभय वरदान साबित हो सकते हैं। सिर्फ़ छात्र ही नहीं अपितु कामगर युवक-युवतियों के लिए भी इग्नू के पाठ्यक्रम भविष्य के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। यहाँ से छात्र कम फ़ीस में अपने मन मर्ज़ी पाठ्यक्रमों में दाख़िला ले सकते हैं तथा आसानी से रोज़गार पा सकते हैं।

किन पाठ्यक्रमों में ले सकते हैं दाख़िला?

स्नातक-स्तरीय पाठ्यक्रम

- कला एवं पर्यटन-अध्ययन में स्नातक, शैक्षणिक योग्यता-किसी भी संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेज़ी/हिंदी। अवधि-तीन वर्ष।
- कंप्यूटर उपयोग में स्नातक (बीसीए)। शैक्षणिक योग्यता-किसी भी संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेज़ी। अवधि-तीन वर्ष।
- सामाजिक कार्य में स्नातक (बीएसडब्ल्यू)। शैक्षणिक योग्यता- किसी भी संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेजी/हिंदी। अवधि-तीन वर्ष।
- कला स्नातक (बीए)। शैक्षणिक योग्यता-किसी भी संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेजी/ हिंदी (अंग्रेजी विषय को छोड़कर)। अवधि-तीन वर्ष।
- विज्ञान स्नातक(बीएससी)। शैक्षणिक योग्यता-विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अवधि-तीन वर्ष।
- वाणिज्य स्नातक (बीकॉम)। शैक्षणिक योग्यता-विज्ञान या वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेज़ी/हिंदी। अवधि-तीन वर्ष। अवधि-तीन वर्ष

परास्नातक-स्तरीय पाठ्यक्रम

- कंप्यूटर-उपयोग में परास्नातक (एमसीए)। शैक्षणिक योग्यता-गणित के साथ स्नातक उत्तीर्ण या कंप्यूटर उपयोग (बीसीए) में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेज़ी। अवधि-दो वर्ष।
- कला एवं ग्रामीण विकास में परास्नातक (एमएआरडी)। शैक्षणिक योग्यता-किसी भी संकाय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेजी/हिंदी। अवधि-दो वर्ष।
- पर्यटन एवं प्रबंधन में परास्नातक (एमटीटीएम)। शैक्षणिक योग्यता-किसी भी संकाय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम-अंग्रेजी। अवधि-दो वर्ष।
- कला (एमए)/विज्ञान (एमएससी)/वाणिज्य (एमकॉम)। संकाय में परास्नातक, शैक्षणिक योग्यता- स्नातक उत्तीर्ण, अवधि-दो वर्ष।
- सामाजिक कार्य (एमएसडब्ल्यू), लोकप्रशासन (एमपीए) में परास्नातक, शैक्षणिक योग्यता-स्नातक उत्तीर्ण, अवधि- दो वर्ष

उपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम :

- आपदा-प्रबंधन, गाँधी एवं शान्ति-अध्ययन, ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, शहरी विकास योजना, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय संचालन, दवा-विक्रय प्रबन्धन तथा अनुवाद आदि में परास्नातक उपाधि। शैक्षणिक योग्यता-स्नातक उत्तीर्ण। माध्यम-अंग्रेज़ी/हिंदी। अवधि-एक वर्ष।
- पत्रकारिता एवं जनसंचार में परास्नातक उपाधि। शैक्षणिक योग्यता-स्नातक उत्तीर्ण एवं पत्रकारिता में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ज़रूरी। माध्यम-अंग्रेज़ी। अवधि-एक वर्ष।
- सृजनात्मक लेखन में परास्नातक उपाधि। शैक्षणिक योग्यता-12वीं उत्तीर्ण। माध्यम-अंग्रेजी। अवधि-एक वर्ष।

प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम :

- सामाजिक कार्य और आपराधिक न्याय पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र। रेशम-उत्पाद पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र। शैक्षणिक योग्यता-स्नातक उत्तीर्ण। माध्यम-अंग्रेजी/हिंदी। अवधि- छह माह।
- साइबर अपराध क़ानून योग्यता पाठ्यक्रम में परास्नातक प्रमाणपत्र। शैक्षणिक योग्यता-स्नातक एवं चतुर्थ व पंचम वर्ष छात्र जो तीन वर्ष एलएल.बी. उत्तीर्ण कर चुके हों। माध्यम-अंग्रेजी। अवधि-छह माह।
- भरतनाट्यम कला पाठ्यक्रम में अदाकारी प्रमाणपत्र। शैक्षणिक योग्यता- दसवीं उत्तीर्ण। माध्यम-अंग्रेजी। अवधि-एक वर्ष।
- अरबी/फ्रांसीसी-भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। शैक्षणिक योग्यता-12वीं उत्तीर्ण। माध्यम-अंग्रेजी/अरबी या अंग्रेजी/हिंदी। अवधि-छह माह।
- प्राकृतिक आपदा पाठ्यक्रम, एचआईवी और परिवार-शिक्षा पाठ्यक्रम, जैविक खेती पाठ्यक्रम, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) प्रबंधन तथा व्यवसाय-कौशल पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र। शैक्षणिक योग्यता-12वीं उत्तीर्ण। माध्यम-अंग्रेज़ी। अवधि-छह माह।

दाख़िला लेने का प्रक्रिया :

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में नामांकन-प्रक्रिया सरल है। इग्नू के द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई-सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन– दोनों है। नामांकन के लिए इच्छुक छात्र किसी भी प्रक्रिया से दाख़िला ले सकते हैं।

- **नामांकन की तिथि (जुलाई 2016 सत्र के लिए)**– बिना विलंब-शुल्क के 17/8/2016 तथा विलंब-शुल्क के साथ 31/8/2016 (कुछ पाठ्यक्रम को छोड़कर)

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें–

रजिस्ट्रार, विद्यार्थी पंजीकरण प्रभाग (एसआरडी)
मैदानगढ़ी, नयी दिल्ली-110 068
फैक्स : 011-29532741, फोन नं. : 011-29532686
www.ignou.ac.in
http://onlineadmission.ignou.ac.in

रोजगार के अवसर :

इग्नू द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों के लिए सरकारी/गैर-सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना है। क्योंकि इग्नू द्वारा परंपरागत पाठ्यक्रम के अलावा तकनीकी क्षेत्रों में भी कई पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जिसकी मांग देश-विदेश में है। इसके अलावा प्रबंधन, एनजीओ, शिक्षा, जैविक खेती, अनुवाद तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि के क्षेत्र में ऐसे छात्रों की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

इग्नू से तकनीकी एवं डिप्लोमा क्षेत्र में पढ़नेवाले छात्रों के लिए समय-समय पर विभिन्न कंपनियों द्वारा परिसर में रोज़गार मेला लगाया जाता है, जिसमें भाग लेकर छात्र लाभान्वित हो सकते है।

कैंपस-सेलेक्शन के बारे विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें :

कैंपस प्लेसमेंट सेल
इग्नू, मैदान गढ़ी, नयी दिल्ली-110 068 (भारत)
ई-मेल : campusplacement@ignou.in ■

योग से मज़बूत हुई भारत की साख

■ शिवानन्द द्विवेदी सहर

ऐतिहासिक मानदण्डों पर योग को देखें तो भारतीय परम्परा में योगविद्या की अवधारणा कोई आज की बात नहीं है। बल्कि भारत में वैदिक काल से ही योगविद्या को स्वस्थ जीवनशैली के लिए जरूरी उपकरण के तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा इतिहासदर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन काल से ही भारत अपनी तमाम विद्याओं एवं पद्धतियों की वजह से विश्वगुरु के रूप में ख्यातिलब्ध रहा है। योगविद्या भी उन्हीं में से एक है। हालांकि समयचक्र के परिवर्तन एवं कालखण्डों में हुए फेर ने ऐसी तमाम भारतीय परम्परागत जीवन-पद्धति के उपकरणों को हाशिये पर लाकर छोड़ दिया, जो किसी ज़माने में हमारे जीवन का अहम हिस्सा हुआ करती थीं। अभी पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रस्ताव को 177 देशों के समर्थन से अनुमति दी थी, जिसमे मोदी ने योग को वैश्विक स्तर पर लाने और अमल करने की बात कही थी। गौरतलब है कि 2014 के अपने अमेरिकी दौरे के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र योग को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लाने के लिए विचार करे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर अमल करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 3 महीने के भीतर ही 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कर लिया। कहीं-न-कहीं इसे प्रधानमंत्री मोदी के मुहीम की सफलता के तौर पर एवं भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। हाशिये पर पड़े इस वैदिक आरोग्य संस्कार के पद्धति को प्रधानमंत्री मोदी ने पुनः वैश्विक मंच पर मज़बूती से स्थापित किया है। योग को स्वीकार करनेवाले सैकड़ों देशों में, उत्तरी अमेरिका के 23 देश, दक्षिणी अमेरिका के 11 देश, यूरोप के 42 देश, एशिया के 40 देश, अफ्रीका के 46 देश एवं अन्य 12 देश शामिल हैं। योग को अन्तरराष्ट्रीय मान्यता के तौर पर स्थापित होने के साथ-साथ वैश्विक इतिहास में दो रोचक घटनाएँ भी हुईं। संयुक्त राष्ट्र में यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि पहली बार कोई प्रस्ताव इतने बड़े बहुमत और इतने कम समय में पारित हुआ है। इस रिकॉर्ड के मायने यही बयाँ करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव पर दुनिया वाकई गंभीर थी और उसी गंभीरता की परिणति थी कि 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिह्नित किया जा सका। हालांकि जब अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर जब पहला 21 जून नज़दीक आ रहा था और दुनिया के 177 देश अपनी स्वीकारोक्ति को अमली जामा पहनाने चुके थे, ऐसे में भारत उनके लिए योग का आदर्श देश बना। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि भारतीय संस्कृति से चिढ़ रखनेवाले कथित वामपंथी एवं तथाकथित सेक्युलर मिज़ाज के राजनीतिक को यह गौरव रास नहीं आया। इन

योग के सन्दर्भ में यदि इसकी वैज्ञानिकता और भारतीय परम्पराओं में इसके वजूद की बात करें तो योग-प्रणाली का ज़िक्र विस्तार से तमाम वैदिक पुस्तकों में मिलता है। कई प्राचीन सभ्यताओं में योग-क्रिया का प्रमाणित दर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में योग तपस्वियों, योगियों एवं आम मनुष्यों के जीवन की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। धीरे-धीरे बाहरी आक्रमणों एवं देश में अस्थिरिता की स्थिति ने इसके महत्त्व को कम कर दिया।

कथित बुद्धिजीवियों एवं सेक्युलरिज़्म की राजनीति का दावा करनेवाले राजनेताओं ने खुद को इससे अलग रखकर यह साबित किया है कि वे भारत की सांस्कृतिक विरासतों से कितना चिढ़ते हैं! सूर्य नमस्कार को लेकर हुए विरोध के बाद सरकार ने इस अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। मगर सवाल यह है कि आख़िर भारत में रहकर भारत की संस्कृति से ही चिढ़ रखनेवालों को क्या कहा जाय ? आख़िर सूर्य कैसे साम्प्रदायिक हो गये, यह समझना असंभव लगता है। वैज्ञानिक तौर पर भी सूर्य प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं एवं सूर्य से हर जाति, धर्म, देश को समान ऊर्जा मिलती है। लेकिन सेक्युलजिज़्म की आड़ में वैमनष्य का प्रपंच बो रहे लोगों को यह बात कभी समझ नहीं आती। सेक्युलरिज़्म बनाम साम्प्रदायिकता की बहस में महत्त्वपूर्ण एवं अहम् मुद्दों का हाशिये पर जाना कोई नयी बात नहीं है। विवाद के केंद्र में योग एवं सूर्य नमस्कार को ही खत्म कर दिया गया जो आज भी प्रासंगिक हो उठता है। बहस यह है कि योग के दौरान सूर्य नमस्कार साम्प्रदायिक है अथवा सेक्युलर? बेशक योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दे दी गई हो एवं दुनिया के सैकड़ों देश इसे अपना चुके हों, लेकिन भारत में ही इसको लेकर विरोध आदि के स्वर बेजा उठाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो व्यक्ति अनुशासित योग-प्रक्रिया का जीवन में अनुकरण करता है, उसे सदैव स्वस्थ रहने का सुख प्राप्त होता है। वैश्विक स्वास्थ्य एवं विदेश नीति के तहत प्रस्तावित किए गए इस एजेंडे में भी मूलतया यही बात कही गई थी कि योग मानव ज़रूरत की तमाम ऊर्जाओं का स्रोत-साधन है। 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने-संबंधी इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह भी कहा गया कि योग को पूरी दुनिया में फैलाना एवं स्थापित करना ज़रूरी है। इस मामले में ग़ौर करनेवाली बात यह भी है कि इस दिवस को 21 जून को ही मनाने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे वैज्ञानिकता यह है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, लिहाज़ा यही दिन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। योग से जुड़े इस प्रस्ताव को पूरी दुनिया ने एकमत होकर स्वीकार किया। दरअसल कम संख्या में ही सही मगर भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में यह पूर्वाग्रह है कि हर परम्परागत संस्कार को वे रुढ़िवादी परम्परा मान बैठते हैं। ऐसी थोड़ी बहुत आलोचनाओं के बीच भारत ने एकबार विश्व को पारम्परिक स्वास्थ्य-प्रणाली का पाठ पढ़ाया है और दुनिया ने इसे स्वीकार भी किया है। योग के सन्दर्भ में यदि इसकी वैज्ञानिकता और भारतीय परम्पराओं में इसके वजूद की बात करें तो योग-प्रणाली का ज़िक्र विस्तार से तमाम वैदिक पुस्तकों में मिलता है। कई प्राचीन सभ्यताओं में योग-क्रिया का प्रमाणित दर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में योग तपस्वियों, योगियों एवं आम मनुष्यों के जीवन की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। धीरे-धीरे बाहरी आक्रमणों एवं देश में अस्थिरिता की स्थिति ने इसके महत्त्व को कम कर दिया। लोग अंग्रेज़ी चिकित्सा-पद्धति पर इतने निर्भर होते गए कि आरोग्य के स्थायी साधन के रूप में योग को शामिल करना ही भूल गये। योग हमे अस्वस्थ होने से बचाता है जबकि दवाइयाँ हमें अस्वस्थ होने के बाद बचाती हैं। इस लिहाज़ से भी देखा जाय तो योग प्राथमिक ज़रूरत है। हालांकि वर्तमान में कुछ नाम ज़रूर प्रासंगिक हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी योग को प्रचारित एवं प्रसारित करने की दिशा में काम किया है। ऐसे कुछ योगगुरुओं का ज़िक्र करें तो श्री तिरुमलाई कृष्णामचार्य, बीकेएस अयंगार, रामदेव कुछ ऐसे ही नाम है जिन्होंने योग को फिर से ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। आधुनिक दौर में योगगुरु रामदेव ने योगशिक्षा को विश्वभर में फैलाने का एक बड़ा काम किया है। हालांकि समय-समय पर योग के महत्त्व को स्वीकार करनेवाले युगपुरुष इस धरा पर जन्म लेते रहे हैं। मसलन, महात्मा गाँधी खुद योग-प्रणाली को स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी मानते थे। चूंकि योग आपसे आर्थिक व्यय की मांग नहीं करता है बल्कि आपके जीवन का कुछ क्षण मात्र ही मांगता है। आज भले ही तमाम तरह के कृत्रिम व्यायाम के उपकरण आ गए हों लेकिन योग में कृत्रिमता का ज़रा भी अस्तित्व नहीं है। योग पूर्णतया प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

आज जब एकबार फिर भारतीय वैदिक परम्परा की यह जीवन-पद्धति विश्व पटल पर स्वीकार की जा रही है, तो इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। विरोध को दरकिनार करते हुए सख़्ती से यह सन्देश देने की ज़रुरत है कि हर बात में सेक्युलरिज़्म की खोखली सियासत नहीं चलेगी। ■

नेशनलिज़्म-राष्ट्र-राष्ट्रीयता-राष्ट्रवाद

सुनील आंबेकर

हम 'भारतमाता की जय', 'वंदेमातरम्' बोलते हैं। हमारे लिए यह मंत्र है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यह संविधान में लिखा है क्या ? लेकिन संविधान लिखने के लिए जो स्वातंत्र्य ज़रूरी था, उसे पाने के लिए-यही मंत्र थे। हमें गर्व है- हमारी बात पर।

नेशनलिज़्म/नेशन– यह शब्द दुनिया के कुछ देशों में बदनाम शब्द है। लेकिन नेशन- राष्ट्र समान अर्थ नहीं है।

नेशनलिज़्म को हिटलर/जर्मन राष्ट्रवाद से जोड़कर उधर देखा जाता है। हमारे राष्ट्रभक्ति को भी जोड़कर हमें 'राष्ट्रवादी' अर्थात् फण्डामेंटलिस्ट बताकर देश की एकता एवं दुनिया की शान्ति के लिए ख़तरा बताते हैं। ऐसा कहना बौद्धिक दिवालियापन है तथा तर्कसंगत नहीं है।

नेशंस के कई प्रयोग हुए। भाषा के आधार पर एक भाषा, एक राष्ट्र, एक वंश बताकर जर्मनी, फ्रांस आदि बने। परंतु इनकी अस्मिताओं के संघर्ष ही हुए। धर्म के नाम राष्ट्र का निर्माण– ऐसे प्रयोग इस्लाम तथा चर्च द्वारा किए गये। काले-गोरे जैसे रंगों पर भी राष्ट्र बने। वंश-जैसी बातों पर भी राष्ट्र बने। लेकिन समाज-रचना का आधार जब 'स्ट्रगल फ़ॉर एग्जिस्टेंस एण्ड सर्वाइवल ऑफ़ फिटेस्ट' बनाया गया तो नये-नये संघर्ष को ही जन्म मिला। वर्चस्व की लड़ाई ही जीवन की रचना का आधार बनी। व्यक्तित्व के लिए पुरुषों और स्त्रियों का संघर्ष आवश्यक हो गया जिसमें एक का ही वर्चस्व रहेगा। भाषाओं का भी संघर्ष चल रहा है जिसमें हारनेवाली भाषा का समाप्त होना निश्चित है। इसी प्रकार राष्ट्र-संघर्ष में एक का वर्चस्व तथा शेष की गुलामी नीयती बन गयी।

पंथों/धर्मों की लड़ाई तथा एक धर्म के ही सत्य एवं शेष धर्म मार्ग उनका दमन आवश्यक हो गया। एक विचारधारा, जैसे कम्युनिष्ट की सफलता के लिए शेष सारे विचार तथा इतिहास को समाप्त होना यह दुराग्रह बन गया।

इसके परिणामस्वरूप पुरी दुनिया को काफ़ी हिंसक घटनाओं आक्रमणों/अत्याचारों को झेलना पड़ा तथा अभी इन पूर्वाग्रहों से जन्मे अन्याय का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिका मजबूत राष्ट्र बनके उभरा, अणुबम गिरा दिया, जर्मनी ने हिटलर दिया। ब्रिटेन की राष्ट्रीय महत्त्वकांक्षा ने दुनिया को गुलाम बनाने का क्रूरतम अपराध किया। उभरते चीन द्वारा तिब्बत पर कब्ज़ा तथा रूस की शक्ति का दंश कम्युनिस्ट हिंसा के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। चीन, रूस तथा पूर्व के कई देशों में किस तरह भयंकर हिंसा का ताण्डव देखने को मिला।

चर्च के राज में भी पूरी दुनिया को ईसाई बनाकर अपने राज्य के अधीन करके इंग्लैण्ड, पुर्तगाल आदि अभियान भी काफ़ी बर्बर थे। खलीफा के शासन से लेकर वर्तमान इस्लामिक स्टेट (आईएस) की नेशन/राष्ट्र कल्पनाओं के नाम पर कैसे मानवताविरोधी कृत्य हो रहे हैं, यह पूरी दुनिया के लिए चिन्ताजनक है।

यह सभी पढ़कर कुछ लोगों ने हमारी राष्ट्र की अवधारणा को भी ग़लत बताया है। लेकिन भारत की राष्ट्र की संकल्पना एवं आराधना काफ़ी पुरानी तथा भिन्न है। वेदों से लेकर रामायण-महाभारत में भी राष्ट्रीय कल्पना हैं। चाणक्य ने भी राष्ट्र के रूप में कल्पना करते हुए राष्ट्रभक्ति को सर्वाधिक पवित्र बताया। शिवाजी, महाराणा प्रताप, आद्य शंकर से लेकर गुरु गोविन्द सिंह, लाचित बड़फूकन सभी ने राष्ट्र आराधना की।

भारत की राष्ट्र की संकल्पना तथा राष्ट्रवाद सकारात्मक भावना है।

भारत का सच्चा ज्ञान क्या था? सामान्य शब्दों में कहा जाए तो 'सभी में भगवान् है'। आज विज्ञान भी सभी भौतिक-जैविक वस्तुओं में समान रूप से गतिमान अणु-रेणुओं के विभिन्न रचनाओं (कॉम्बिनेशन) की पुष्टि कर रहा है। जब हम यह मान लेते हैं कि सभी में एक ही तत्त्व है तो हम अलग-अलग नहीं रह जाते, हमारा आपस में नज़दीक का रिश्ता बन जाता है। हमारा मनुष्यों, प्राणी, वनस्पति, नदी-नालों तथा पहाड़ों से रिश्ता बन जाता है। जब रिश्ते बन जाते हैं तो हम फिर उनसे संघर्ष की नहीं, प्यार की सोचने लगते हैं। संघर्ष एवं हारनेवाले के अस्तित्व समाप्ति के बदले **'सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः'** सोचना प्रारंभ होता है।

सभी में एकात्मता के सूत्र ढूँढने की भारत की प्रवृत्ति को ही भारतीय संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति माननेवाले सैकड़ों वर्षों की साधना से एक संस्कृति पर आधारित एक राष्ट्र बन जाते हैं- जिसका नाम भारत है। 'यूनिटी इज डायवर्सिटी'– इसका अर्थ कि हम अलग (डाइवर्ट) है तथा इन्हें एक करना है। परंतु हम मानते हैं कि हम एक ही हैं और विभिन्न रूपों में प्रकट हैं। इसलिये हमारी राष्ट्रीयता एकात्मता भी अलग-अलग बातों को जोड़कर नहीं बनी, अपितु हम संस्कृति से एक है– इसलिए हम एक राष्ट्र है।

जीवन में एक-दूसरे में भेद के स्थान पर अंदर की समानता नज़र आने लगती है। अलग-अलग भाषाएँ तमिल-पंजाबी होने पर भी एक राष्ट्र संभव होता है। इडली-वड़ा तथा पराठा खानेवाले, ऊँचे-नीचे, काले-गोरे सभी एक राष्ट्र संभव हो जाता है। सभी में एकात्मता के सूत्र ढूँढने की भारत की प्रवृत्ति को ही भारतीय संस्कृति कहते हैं। इन रिश्तों की कल्पना ही हमारी संस्कृति है। यह संस्कृति माननेवाले सैकड़ों वर्षों की साधना से एक संस्कृति पर आधारित एक राष्ट्र बन जाते हैं- जिसका नाम भारत है। 'यूनिटी इज डायवर्सिटी'– इसका अर्थ कि हम अलग (डाइवर्ट) है तथा इन्हें एक करना है। परंतु हम मानते हैं कि हम एक ही हैं और विभिन्न रूपों में प्रकट हैं। इसलिये हमारी राष्ट्रीयता एकात्मता भी अलग-अलग बातों को जोड़कर नहीं बनी, अपितु हम संस्कृति से एक है– इसलिए हम एक राष्ट्र है। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। एक ही घर में दो भाई-बहन अलग दिखते हैं। एक होने पर भी अलग-अलग दिखना यह प्रकृति की विविध रूपों में प्रकट हुई सुंदरता है। हमारा राष्ट्र जब उभरता है (राइसेस) मज़बूत होता है तब वह वर्चस्व, अन्याय, अत्याचार को जन्म नहीं देता है। भारत जब मज़बूत है तो योग-आयुर्वेद का ज्ञान जन्म लेता है। **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** की पुकार स्वाभाविक रूप से निकलकर आती है। इसलिए भारत का राष्ट्र-राष्ट्रीयता-राष्ट्रवाद पूरी दुनिया के चिर वरदान है।

वीर सावरकर के अनुसार यह संस्कृति ही हमारा स्वधर्म है तथा इसकी रक्षा हेतु समग्र स्वाधीनता महत्त्वपूर्ण शर्त है। इसलिए ऐसे स्वधर्म की रक्षक स्वाधीनता के लिए जीना-मरना हर युग में धर्म कर्तव्य है। यह भारत शक्ति विश्वकल्याण हेतु है। इसलिए हमारी राष्ट्र आराधना तथा इस हेतु चली अखण्ड साधना पवित्र, आवश्यक एवं 21वीं शती में भी प्रासंगिक है। भारतमाता की जय।

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है)

■

ग्रामीण पत्रकारिता के लिए आशीष अंशु को नारद सम्मान

नयी दिल्ली। आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयन्ती के अवसर पर इन्द्रप्रस्थ विश्व संवाद केन्द्र द्वारा नारद पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें पत्रकारिता के विविध क्षेत्रों में बेहतर कार्य करनेवाले आठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वर्ष 2015-'16 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देनेवाले पत्रकारों को सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र संघचालक डॉ. बजरंगलाल गुप्त ने सम्मानित किया।

इस क्रम में आशीष कुमार 'अंशु' को ग्रामीण पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित 'महर्षि नारद पत्रकारिता सम्मान' से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आशीष कुमार 'इण्डिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टडी' से संबद्ध हैं। साथ ही एक मासिक पत्रिका 'सोपान स्टेप' के लिए नियमित लेखन करते हैं। विदित हो कि आशीष कुमार 'अंशु' राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका से भी बतौर सहायक संपादक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं।

जेएनयू रजिस्ट्रार व अन्य से हुई पूछताछ

नयी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिर से जाँच शुरू कर दी है। पुलिस-सूत्रों के मुताबिक सेल के तीन इंस्पेक्टरों की टीम जेएनयू कुलपति के कार्यालय पहुँची। टीम ने रजिस्ट्रार, डीन (छात्र कल्याण) समेत कई अधिकारियों से घंटों पूछताछ की। सेल की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि कन्हैया कुमार व उमर खालिद को बीते 9 फरवरी की रात संसद हमले के दोषी अफज़ल गुरु की बर्सी पर सांस्कृतिक संध्या आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी कार्यक्रम का कैसे आयोजन किया गया।

सेल के एक अधिकारी के मुताबिक निजी चैनल के वीडियो से छेड़छाड़ की बात कह कुछ लोगों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद इसे जाँच के लिए सीबीआइ की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। एक सप्ताह पहले फॉरेंसिक लैब से देशविरोधी नारे लगाने से संबंधित वीडियो फुटेज की रिपोर्ट आने के बाद मामले की जाँच फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। वीडियो में उमर खालिद समेत कई आरोपियों की तस्वीरें देशविरोधी नारे लगाते हुए कैद हैं। इसके अलावा कई छात्र-छात्रओं ने आइफोन व अन्य मोबाइल के जरिए भी वीडियो बनाए थे। इनमें से चार वीडियो जाँच में सही पाए गये।

छत्तीसगढ़

देश का पहला विद्युत कटौती मुक्त राज्य...

उद्योगों सहित घरेलू उपयोग और खेती-किसानी के लिए 24×7×365 बिजली देने वाला राज्य

- विद्युत उत्पादन क्षमता 71 प्रतिशत बढ़कर 2424 मेगावाट हुई
- प्रति उपभोक्ता विद्युत खपत 220 प्रतिशत बढ़कर 1600 यूनिट
- बीपीएल उपभोक्ता 146 प्रतिशत बढ़कर 16 लाख हुए
- 400 KV लाईन में 455 प्रतिशत की वृद्धि, अब 1538 सर्किट किलोमीटर
- 220 KV लाईन 3314 सर्किट किलोमीटर, 104 प्रतिशत की वृद्धि
- सिंचाई पम्प कनेक्शन - 3.46 लाख, 297 प्रतिशत बढ़े
- 18520 ग्राम पूर्णतः विद्युतीकृत, 25595 मजरों-टोलों तक पहुँची बिजली

RNI 32464/78

अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस 26 जून

युवा मन को समझें

नशा छोड़ने के लिये
जरूरत है,
बस एक इरादे की...
क्योंकि, इरादे के आगे
टिकती नहीं कोई मुश्किल

नशे को कहें ना
जीवन को कहें हाँ ✓

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जनहित में जारी